●वर्ष-5
●अंक-227
रायपुर, रविवार
10 मई 2026
●पृष्ठ-8
●मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› शुभेंदु बने नए सीएम, साय ने दी बधाई

बंगाल के अधिकारी बने शुभेन्दु

मोदी-शाह की उपस्थिति में राज्यपाल ने दिलाई पद की शपथ

कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जुझारू नेता शुभेन्दु अधिकारी ने शनिवार को यहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार के गठन के साथ राजनीति का एक नया अध्याय शुरु हुआ है और तृणमूल कांग्रेस के 15 वर्ष के शासन का अंत हो गया है।

छप्पन वर्षीय श्री अधिकारी को राज्यपाल आर एन रवि ने ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में आयोजित भव्य समारोह में विशाल जन समूह के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी। उनके साथ श्री दिलीप घोष, सुश्री अग्निमित्रा पॉल, श्री अशोक कीर्तनिया, श्री खुदीराम टुडू और श्री निसिथ प्रमाणिक को भी मंत्री पद की शपथ दिलायी गयी।शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और भाजपा तथा उसके नेतृत्ववाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासन वाले विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगातार दो चुनावों में शिकस्त देने वाले श्री अधिकारी को शुक्रवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नेता चुना गया था।उन्नीस सौ पचास के दशक में गठित जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राजनीतिक विरासत और विचारधारा की वाहक भाजपा पश्चिम बंगाल में 20 16 से पहले राजनीतिक हाशिए पर थी। वर्ष 2016 के विधान सभा चुनाव में उसने पहली बार तीन सीटों के साथ अपना खाता खोला था और 2021 के चुनाव में पार्टी ने 77 सीटें जीत कर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त किया।राज्य में भाजपा के उदय के साथ वर्षों से सत्ता में रहे कांग्रेस और वामपंथी दल हाशिए पर चले गये।शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर कविवर रवींद्र नाथ टैगोर का चित्र लगा हुआ था जिनकी आज जयंती मनायी जा रही है। प्रधानमंत्री ने मंच पर पहुंचते ही उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके बाद श्री अधिकारी ने भी साहित्य के नोबेल से सम्मानित गुरुदेव को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने मंच से राज्य की जनता को दंडवंत प्रणाम किया। उन्होंने मंच पर ही पश्चिम बंगाल में भाजपा के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में से एक माखनलाल सरकार का शॉल ओढ़ा कर अभिनंदन किया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। श्री अधिकारी ने कल भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पश्चिम बंगाल के पुर्निर्माण का संकल्प लेते हुए कहा था कि भाजपा सरकार राज्य की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगी।उल्लेखनीय है कि बंगाल एक समय देश का अग्रणी औद्योगिक राज्य था लेकिन राजनीतिक माहौल के चलते धीरे धीरे पिछड़ता गया । इसके अलावा राज्य में घुसपैठिए, हिंसा, भ्रष्टाचार , बेरोजगारी, महिला सुरक्षा को भी भाजपा नेताओं ने ममता सरकार के विरुद्ध प्रमुख मुद्दा बनाया था।

पांच अन्य नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ

सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। सुवेंदु अधिकारी के बाद पांच अन्य नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। इन मंत्रियों के मंत्रालय अभी तय नहीं किए गए हैं।दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, क्षुदीराम टुडू, निसिथ प्रामाणिक।

आज होगा विजय शपथ!

वीसीके ने बिना शर्त टीवीके को अपना समर्थन देने का ऐलान

चेन्नई। तमिलनाडु में विदुथलाई चिरूथईगल काट्ची (वीसीके) ने तमिझगा वेट्री कषगम (टीवीके) को सरकार बनाने के लिए बिना शर्त अपना समर्थन देने का ऐलान शनिवार शाम को कर दिया। वीसीके के इस कदम से राज्य में नयी सरकार के गठन को लेकर पिछले एक सप्ताह से जारी राजनीतिक खींचतान पर विराम लग गया।

श्री थोल थिरुमावलवन के नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टी वीसीके बीते कुछ दिनों से टीवीके को समर्थन देने के मसले पर काफी उहापोह में थी। हालांकि उसके पास 234 सदस्यीय विधानसभा में केवल दो विधायक हैं लेकिन उसका रूख स्पष्ट न होने के कारण टीवीके को बहुमत हासिल करने में अड़चन आ रही थी पर अब समर्थन के ऐलान के बाद टीवीके और उसके नेता जोसेफ विजय को सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का जादुई आंकड़ा प्राप्त हो गया है। नेता थिरुमावलवन के, टीवीके चुनाव अभियान प्रबंधन महासचिव आधाव अर्जुना को समर्थन पत्र सौंपने के बाद की गई।

समर्थन पत्र प्राप्त करने के बाद श्री अर्जुना ने मीडिया से कहा, विजय, विजय, विजय। मैं कांग्रेस, भाकपा, माकपा के नेताओं और अपने राजनीतिक गुरु थिरुमावलवन को धन्यवाद देता हूं। लोकतंत्र की रक्षा की जाएगी और हमारे नेता विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री होंगे।

गौरतलब है कि अभिनेता से नेता की भूमिका में आए जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही चुनाव में 108 सीटों पर जीत दर्ज की, हालांकि दो सीटों से चुनाव जीतने के कारण तकनीकी रूप से उनके पास 107 विधायक थे और उन्हें बहुमत के लिए 11 और सदस्यों की आवश्यकता थी। इस कमी को पूरा करने के लिए श्री विजय ने विपक्षी गठबंधन के सहयोगियों से संपर्क साधा, जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों के साथ द्रमुक का साथ छोड़कर टीवीके को समर्थन दिया, जबकि माकपा और भाकपा ने अपने 2-2 विधायकों के साथ बाहर से समर्थन देने का फैसला किया। अंतत: वीसीके के 2 विधायकों के बिना शर्त समर्थन के साथ टीवीके गठबंधन की कुल संख्या 118 (107 5 2 2 2) तक पहुँच गई, जो सरकार बनाने के लिए आवश्यक जादुई आंकड़ा है।वीसीके के फैसले को लेकर सुबह से ही काफी उत्सुकता बनी हुई थी। श्री थिरुमावलवन ने सुबह अपना निर्णय टाल दिया था, जिससे राजनीतिक गलियारों में बेचैनी बढ़ गई थी। हालांकि, शाम होते-होते उन्होंने दो विधायकों के समर्थन की पुष्टि कर दी। रिपोर्टों के अनुसार, यह समर्थन काफी गहन चर्चा और राजनीतिक मोलभाव के बाद आया है।अब राज्यपाल विजय को औपचारिक रूप से सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय की जाएगी

रायपुर। एयरपोर्ट परिसर भारत माता की जय एवं वंदे मातरम् के नारों से गूंज उठा. रायपुर- पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय के बाद राजधानी रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के रायपुर आगमन पर स्वामी विवेकानंद विमानतल में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला।

आज योगी कैबिनेट विस्तार, 6 विधायकों को मिल सकती है जगह

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मंत्री बनने की आस लगाए विधायकों के दिलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। योगी कैबिनेट का कल विस्तार होनेवाला है। आज शाम सीएम योगी ने राज्यपाल से मुलाकात की है। कल दोपहर बाद तीन बजे नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट विस्तार में छह नए मंत्री बनाये जा सकते हैं। यूपी में विधायकों की संख्या के हिसाब से 60 मंत्री हो सकते हैं।

6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं

लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद और राज्यमंत्री रहे अनूप प्रधान वाल्मिकी सांसद बन गए। मुख्यमंत्री,दो उपमुख्यमंत्री समेत अभी मंत्रिमंडल में 54 सदस्य ही हैं। इनमें 21 कैबिनेट,14 स्वतन्त्र प्रभार और 19 राज्यमंत्री हैं। इस तरह योगी मंत्रिमंडल में अभी छह और मंत्री बनाये जा सकते हैं।सूत्रों के मुताबिक पहले पार्टी आलाकमान कुछ मंत्रियों को हटाने पर विचार कर रहा था,लेकिन अब कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं किया जाएगा । सिर्फ छह विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अब कौन बनेगा मंत्री? इसको लेकर अटकलों का बाज़ार गर्म है। 2024 में हुए राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सात विधायकों ने बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग की थी। माना जा रहा है कि इनमें से दो मनोज पांडेय और पूजा पाल को मंत्री बनाया जा सकता है। मनोज पांडेय ब्राह्मण है और पूजा पाल ओबीसी।

पूजा पाल इलाहाबाद से पूर्व विधायक राजू पाल की पत्नी हैं। माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ राजू पाल की हत्या का मुख्य आरोपी था। पूजा पाल ने 2022 का विधान सभा सपा के टिकट पर लड़ा था लेकिन राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट किया था और विधान सभा में अखिलेश यादव के ख़िलाफ़ बयान दिया था जिसके बाद पिछले साल अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था।

इसके अलावा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रहे भूपेंद्र चौधरी का भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। वहीं कृष्णा पासवान,अशोक कटारिया को भी मंत्री बनाया जा सकता है। सुरेन्द्र दिलेर का नाम भी चर्चा में है। वहीं हंसराज विश्वकर्मा और आशा मौर्य का नाम भी मंत्री पद के लिए चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक कुछ मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल भी हो सकता है। योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री बने थे। इस दौरान यूपी कैबिनेट का पहला विस्तार मार्च 2024 में हुआ था। अब 2027 में यूपी में विधान सभा का चुनाव है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार में क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का खास ध्यान रखा जाएगा।

प्रमुख समाचार

उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल उड़ान-परीक्षण

नयी दिल्ली। भारत ने अनेक सामरिक लक्ष्यों पर एक साथ निशाना लगाने वाली उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल उड़ान-परीक्षण किया है।रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि यह परीक्षण शुक्रवार को ओडिशा के डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से बहु-स्वतंत्र लक्ष्यित वाहन (एमआईआरवी) प्रणाली से किया। यह उड़ान-परीक्षण अनेक पेलोड के साथ किया गया, जिन्हें हिन्द महासागर क्षेत्र में विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में स्थानिक रूप से फैले विभिन्न लक्ष्यों पर निर्देशित किया गया था।परीक्षण की टेलीमेट्री और ट्रैकिंग अनेक भू-आधारित तथा पोत-आधारित स्टेशनों द्वारा की गई। इन प्रणालियों ने प्रक्षेपण से लेकर सभी पेलोड के प्रभाव तक मिसाइल की पूरी उड़ान-पथ पर नजर रखी। उड़ान संबंधी आँकड़ों ने पुष्टि की कि परीक्षण के दौरान मिशन के सभी उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त किए गए।इस सफल परीक्षण के साथ भारत ने एक बार फिर एकल मिसाइल प्रणाली के माध्यम से अनेक सामरिक लक्ष्यों को साधने की क्षमता का प्रदर्शन किया।

आप के उगाही तंत्र के सरगना हैं केजरीवालः सचदेवा

नयी दिल्ली। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी (आप) के उगाही तंत्र का सरगना बताया है।श्री सचदेवा ने शनिवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए आप के पंजाब के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के छापे को लेकर श्री केजरीवाल के बयान की निंदा की।उन्होंने कहा कि श्री केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर ईडी के छापे को राजनीतिक साजिश करार दिया हैं।संवाददाता सम्मेलन के दौरान केजरीवाल के चेहरे की हवाईयां उड़ रही थी और साफ तौर पर दिखा रहा था कि वह जान रहे हैं कि यह ईडी की जांच अरोड़ा से होते हुए उन तक भी पहुंचेगी, क्योंकि इस सारे उगाही तंत्र के सरगना तो खुद केजरीवाल ही प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह पंजाब में मंत्री अरोड़ा हवाला कारोबार के मामले में गिरफ्तार हुए हैं, यह बिल्कुल वैसे है जिस तरह दिल्ली ने दस साल भ्रष्टाचार की सरकार झेली जिसमें मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री, सांसद शराब घोटाले में जेल गये।

पारसी समुदाय की विरासत को संरक्षित करना सरकार की प्राथमिकताः रिजिजू

नयी दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पारसी समुदाय की विरासत को संरक्षित करने और उनकी घटती जनसंख्या से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री रिजिज ने मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) के राष्ट्रीय संगोष्ठी में आज पारसी समुदाय की विरासत को संरक्षित करने और उनकी घटती जनसंख्या से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। पारसी समुदाय ने भारत के औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया है। सरकार पारसी आबादी में गिरावट की समस्या से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, यह केवल संख्या का विषय नहीं है, बल्कि प्रभाव का महत्व है। सरकार हर समुदाय को महत्व देती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है।

नेपाल को भारत ने दिया 440 वोल्ट का झटका, रद्द किया दौरा

नईदिल्ली। लिपुलेख वो इलाका है जो भारत का है और नेपाल इसे लेकर उल्टे सीधे दावे करता है और पिछले कुछ दिनों में नेपाल में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो गई। ऐसे में विदेश सचिव का दौरा टलना इन घटनाओं का भी प्रभाव हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि भारत तक नहीं करता। आपको बता दें भारत और नेपाल के संबंध सिर्फ पड़ोसी देशों वाले नहीं है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है। सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव है और आर्थिक सहयोग भी दोनों के बीच काफी बड़ा रोटी बेटी का रिश्ता है। पिछले कुछ दिनों में भारत और नेपाल के रिश्तों में हल्का तनाव देखने को मिला। पहले लिपुलेख को लेकर विवाद जहां दोनों देशों की ओर से बयानबाजी हुई और अब खबर आ रही है कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री का प्रस्तावित नेपाल दौरा फिलहाल टाल दिया गया। बताया जा रहा है कि यह दौरा 11 मई से शुरू होना था। लेकिन अचानक इसे स्थगित कर दिया गया और भारत की ओर से लिए गए इस फैसले को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। दरअसल विदेश सचिव विक्रम मिश्री दो दिन के दौरे पर काठमांडू जाने वाले नेपाल और भारत दोनों तरफ से इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई थी।

वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन नये सेना प्रमुख नियुक्त

नयी दिल्ली। लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि (सेवानिवृत्त) को प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) और वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों में इन महत्वपूर्ण नियुक्तियों की शनिवार सुबह घोषणा की। लेफ्टिनेंट जनरल राजा सब्रमणि जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका 30 मई को कार्यकाल पूरा हो रहा है जबकि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की जगह नौसेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभालेंगे जो 31 मई को सेवा निवृत हो रहे हैं। ले जनरल सुब्रमणि सैन्य कार्य विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे और उनकी नियुक्ति उनके कार्यभार संभालने के दिन से प्रभावी मानी जायेगी और वह अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणि एक सितंबर 2025 से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले वह 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2025 तक सेना के उप प्रमुख रहे तथा मार्च 2023 से जून 2024 तक केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ रहे।

अब 2029 की तैयारी

सुवेंदु से टुडु तक बंगाल में भाजपा ने एक साथ साधे कई समीकरण

कोलकाता । बंगाल में सरकार गठित करते ही भाजपा 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। उसने अपने पहले मंत्रिमंडल के गठन से यह स्पष्ट कर दिया है। सुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री और दिलीप घोष, अग्निमित्रा पाल, निशिथ प्रमाणिक, अशोक कीर्तनिया व खुदीराम टुडू को मंत्री बनाकर पार्टी ने जाति, क्षेत्र, संगठन और सामाजिक समीकरणों को एक साथ साधा है।

जंगलमहल से पूरे बंगाल का चेहरा

नंदीग्राम के भूमिपुत्र सुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने सबसे बड़ा संदेश दिया कि आंदोलन और संगठन चलाने वाला नेता ही सरकार का नेतृत्व करेगा। सुवेंदु की ताकत पूर्व व पश्चिम मेदिनीपुर, झाडग्राम, पुरुलिया का जंगलमहल इलाका है, जहां हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 38 में से 34 सीटें जीतीं। संदेश साफ है ममता के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को मुख्यमंत्री बनाकर तृणमूल कांग्रेस के कोर मतदाताओं व कार्यकर्ताओं में सेंध लगाना।वहीं खडगपुर सदर से विधायक दिलीप घोष को मंत्री बनाकर भाजपा ने संगठन के पुराने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया है।

2015 से 2021 तक प्रदेश अध्यक्ष रहते घोष ने ही बंगाल में पार्टी को खड़ा किया था। घोष को मंत्रिमंडल में शामिल करके भाजपा ने आरएसएस के कैडरों को भी संदेश दिया कि संगठन की भूमिका सरकार में बराबर रहेगी।

महिलाओं को साधने की जुगत

आसनसोल दक्षिण से दूसरी बार विधायक बनीं अग्निमित्रा पाल बंगाल भाजपा की सबसे मुखर महिला चेहरा हैं। फैशन डिजाइनर से राजनीति में आईं अग्निमित्रा शहरी, पढ़ी-लिखी महिला मतदाताओं को आकर्षित करती हैं। उन्हें मंत्री बनाकर पार्टी ने महिला सशक्तीकरण और शहरी मध्यवर्ग की आवाज बनने का भी संदेश दिया है।

दिनहाटा से विधायक निशिथ प्रमाणिक को मंत्री बनाना उत्तर बंगाल पर भाजपा की पकड़ मजबूत करने की रणनीति है। राजबंशी समुदाय से आने वाले निशिथ की उत्तर बंगाल की 30 में से 25 सीटें जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुके निशिथ सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ का मुद्दा उठाते रहे हैं। उनके जरिए भाजपा ने राजबंशी मतदाताओं को संदेश दिया कि उत्तर बंगाल सरकार की प्राथमिकता में रहेगा।

मतुआओं के मत पर भी नजर

बनगांव उत्तर से विधायक अशोक कीर्तनिया को मंत्री बनाकर भाजपा ने मतुआ समुदाय को साधा है। मतुआ बंगाल की 17 प्रतिशत आबादी हैं और उत्तर 24 परगना व नदिया जिलों में निर्णायक हैं।

कीर्तनिया खुद मतुआ समुदाय के धार्मिक आयोजनों में सक्रिय रहते हैं। भाजपा ने उन्हें कैबिनेट में रखकर सीमावर्ती इलाकों और शरणार्थी वोटरों को संदेश दिया कि नागरिकता कानून सिर्फ चुनावी वादा नहीं, नीति का हिस्सा बनेगा।

आदिवासियों का भरोसा जीतने की जुगत

रानीबांध के विधायक खुदीराम टुडू को मंत्री बनाकर भाजपा ने आदिवासी समाज को प्रतिनिधित्व दिया है। जंगलमहल में आदिवासी वोटरों की संख्या निर्णायक है। 2021 में यहां भाजपा ने अच्छी बढ़त बनाई थी। 2026 में उसकी स्थिति और मजबूत हुई है। खुदीराम की छवि शांत और जमीनी नेता की है। उनके जरिए भाजपा ने दिखाया कि आदिवासी विकास सरकार की प्राथमिकता में है।

बस्तर के जंगल में दबा है लाल आतंक का खजाना

■ माओवादियों के डंप को खोजना है बड़ी चुनौती

बस्तर। बस्तर में अब भी माओवादी संगठन द्वारा डंप में छुपाए गए लेवी के करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। बीते 3 महीनों में ही पुलिस ने करीब 18-20 करोड़ माओवादियों के डंप से बरामद किया है। नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन के बाद पुनर्वास कर रहे माओवादी अपने साथ न केवल हथियार बल्कि सोना और नगद राशि भी लेकर पहुंचे। इसके अलावा माओवादियों के कई डंप सामग्री अब भी जंगल में मौजूद हैं। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि बीते दिनों माओवादियों द्वारा गलत तरीके से स्थानीय लोगों और अन्य क्षेत्रों से वसूल किये गए डंप को पुलिस ने बरामद किया है। तीन महीने के अंदर फोर्स के जवानों ने तकरीबन 6 करोड़ 75 लाख रुपए नगद और 8 किलोग्राम सोना भी बरामद किया है। पुलिस द्वारा बरामद 8 किलोग्राम सोना की कीमत तकरीबन 13 करोड़ रुपए आंकी गई है। सोना और कैश दोनों मिलाकर करीब 18-20 करोड़ माओवादियों के डंप से बरामद किया गया है। आने वाले दिनों में भी पुलिस के जवान माओवादियों के विभिन्न डंप इलाकों में पहुंचेंगे और उन्हें बरामद करके माओवादियों के फंड फ्लो को पूरी तरह समाप्त करेंगे- सुंदरराज पी, बस्तर आईजी नक्सल एक्सपर्ट और बस्तर के जानकारों के मुताबिक तेंदुपत्ता के ठेकेदारों से नक्सलियों की वसूली लाखों रुपयों में होती थी। वो गांव वालों से भी पैसा वसूलते थे। वरिष्ठ पत्रकार व जानकार राजेंद्र तिवारी ने बताया कि माओवादी बस्तर में तोड़े जाने वाले हरा सोना (तेंदूपत्ता) के ठेकेदारों से ही लाखों रुपये की वसूली अलग अलग क्षेत्रों से करते थे। जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और सरकारी नौकरी के साथ ही वाहनों की खरीदी करने वाले ग्रामीणों से भी नक्सली वसूली करते थे। जंगल में अब तक फोर्स द्वारा बरामद किया गया पैसा और सोना सिर्फ बानगी है। माओवादी संगठन के पास सिर्फ बस्तर में ही कम से कम 50 करोड़ रुपए होने चाहिए-राजेंद्र तिवारी, बस्तर के जानकार बस्तर के जानकार राजेंद्र तिवारी ने बताया कि विशेषकर दक्षिण भारत के ठेकेदार, जिन्हें तेंदुपत्ता का टेंडर मिल जाता था, वो नक्सलियों को मुंहमांगी रकम देते थे। गांव वालों से भी लेवी वसूली जाती थी।

एक करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी, राजस्थान से दो आरोपी पकड़ाए

बिलासपुर। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 1 करोड़ 4 लाख 80 हजार रुपए की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के दो आरोपियों को रेंज साइबर थाना बिलासपुर की टीम ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर बिलासपुर लाया गया है।

पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने एक महिला को पुलिस, ईडी, आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का डर दिखाकर ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया। मामले में रेंज साइबर थाना बिलासपुर में केस दर्ज किया गया है। पीड़िता के परिवार द्वारा दर्ज रिपोर्ट के अनुसार महिला के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को संजय [illegible] बताया। आरोपी ने महिला को कहा कि उनका नाम एक आतंकवादी संगठन से जुड़े मामले में सामने आया है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है।

इसके बाद वीडियो कॉल के जरिए महिला को घंटों तक तथाकथित डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। आरोपियों ने पुलिस, ईडी, आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट का भय दिखाकर महिला पर लगातार मानसिक दबाव बनाया। आरोपियों ने महिला को फर्जी सरकारी नोटिस, ईडी जांच दस्तावेज, सुप्रीम कोर्ट आदेश और आरबीआई नोटिस भेजे। साथ ही परिवार से संपर्क करने पर बेटे और अन्य रिश्तेदारों को भी मामले में फंसाने की धमकी दी गई। लगातार डर और दबाव के चलते महिला आरोपियों के झांसे में आ गई। आरोपियों ने अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कराई।

अलग-अलग तिथियों में कुल 1 करोड़ 4 लाख 80 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। इतना ही नहीं, आरोपियों द्वारा केस खत्म कराने के नाम पर अतिरिक्त 50 लाख रुपये की मांग भी की जा रही थी। बाद में महिला ने अपने पुत्र को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद मामला सामने आया और साइबर थाना बिलासपुर में शिकायत दर्ज कराई गई।

जांजगीर-चांपा में पीएम श्री स्कूल की हेड मास्टर निलंबित

जांजगीर चाम्पा। जिले के बलौदा ब्लॉक के पीएम श्री कन्या प्राथमिक शाला के हेड मास्टर के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन की कार्रवाई की है। महिला हेड मास्टर लक्ष्मी देवी भारद्वाज पर छात्राओं को धर्मांतरण को लेकर उकसाने का आरोप था। इसके साथ ही वित्तीय अनियमितता की भी बात सामने आई थी। बताया जा रहा है कि हेड मास्टर के खिलाफ आरोप की जांच हुई लेकिन इसके बाद भी विभाग ने चुप्पी साध रखी थ। इस पर भिलाई गांव में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों ने पुराने शिकायत पर ही कार्रवाई नहीं होने की बात बताई। इस पर शासन के कडे निर्देश के कारण आखिरकार जिला शिक्षा अधिकारी ने [illegible] की जांच रिपोर्ट पर निलंबन की कार्रवाई की है। स्कूल के छात्राओं ने परिजनों और अभिभावकों को जानकारी दी थी कि स्कूल की हेड मास्टर लक्ष्मी देवी भारद्वाज प्रार्थना के दौरान राष्ट्रीय गीत नहीं बल्कि अलग तरह की प्रार्थना सभा कराती है। इसमें एक धर्म विशेष को लेकर छात्राओं को मोटिवेट करती है। हिन्दू देवी देवताओं के प्रति अपमानित करने वाले प्रवचन कहती है। आरोपों के मुताबिक हेड मास्टर प्रसाद नहीं खाने और पूजा पाठ नहीं करने पर दबाव भी बनाती थी। इसकी शिकायत परिजनों और बजरंग दल ने बलौदा थाना में की थीं, जिस पर बलौदा पुलिस ने छात्राओं को एक मिशनरी प्रार्थना सभा से हेड मास्टर के साथ पाया। इसके अलावा हेड मास्टर लक्ष्मी देवी भारद्वाज पर शाला विकास समिति से प्रस्ताव लिए बिना ही फर्जी बिल वाउचर बनाकर राशि निकालने का भी आरोप है। अभिभावकों ने हेड मास्टर की शिकायत में कुछ वीडियो भी दिए थे जो उस स्कूल के बच्चों से प्रार्थना के दौरान कराया जाता था। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा ने जारी आदेश में बताया कि इस मामले में शिकायत पर जांच टीम गठित की गई थी। इसकी जांच बलौदा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई, मामला फिर से भिलाई गांव में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में आया और जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच रिपोर्ट के आधार पर हेड मास्टर लक्ष्मी देवी भारद्वाज को निलंबित कर [illegible] कार्यालय बलौदा में उपस्थिति देने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम द्वारा घूसखोर पटवारी निलंबित

■ सोशल मीडिया में पटवारी के घूस लेने का वीडियो वायरल हुआ था.इस वीडियो के बाद प्रशासन ने पटवारी के खिलाफ एक्शन लिया है.

दुर्ग। दुर्ग कलेक्टर ने रिश्वत लेने वाले वीडियो पर कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने त्वरित कार्रवाई करते आरोपी पटवारी को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया में पटवारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था।इस वीडियो की सत्यता जांचने के बाद पटवारी को निलंबित किया गया है। पूरा मामला भूमि बंटवारे के एवज में रकम लेने से जुड़ा है। भिलाई 3 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने तहसील कार्यालय में पदस्थ पटवारी लेकेश्वर सिंह ठोकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।आदेश में कहा गया है कि कर्मचारी पर कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही और आचरण नियमों के उल्लंघन के आरोप पाए गए हैं। निलंबन अवधि के दौरान संबंधित पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय अहिवारा निर्धारित किया गया है। नियमानुसार पटवारी को जीवन निर्वाह भत्ता भी दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था।इसमें राजस्व विभाग से जुड़े कर्मचारी पर पैसे लेने के आरोप लगा था। वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल जांच के निर्देश दिए।जांच की जिम्मेदारी तहसील स्तर पर अधिकारियों को सौंपी गई। जांच के दौरान संबंधित भूमिस्वामी, पक्षकार और हल्का पटवारी के बयान दर्ज किए गए। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि पटवारी भूमि बंटवारे की प्रक्रिया के बदले कथित रूप से 45 हजार रुपए की राशि लेकर काम नहीं कर रहा था।इसके बाद पीड़ित ने पटवारी लेकेश्वर सिंह ठाकुर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था।

एसपी ने 13 अधिकारियों का किया तबादला

धमतरी। धमतरी पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने पुलिस विभाग में एक व्यापक फेरबदल किया है। जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, जिले के 13 पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

इस सूची में निरीक्षक, उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

प्रशासनिक फेरबदल के तहत सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जिला मुख्यालय और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखा गया है। निरीक्षक राजेश जगत जो अब तक अर्जुनी थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत थे, उन्हें अब धमतरी शहर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए थाना प्रभारी सिटी कोतवाली धमतरी नियुक्त किया गया है। वहीं, कुरूद के थाना प्रभारी रहे निरीक्षक चन्द्रकांत साहू को अब अर्जुनी थाने की कमान सौंपी गई है। इसके साथ ही उन्हें सायबर पुलिस थाना का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

जिले के वनांचल और ग्रामीण थाना क्षेत्रों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। रक्षित केंद्र (लाइन) में पदस्थ निरीक्षक अवधराम साहू को कुरूद थाने का नया प्रभारी बनाया गया है।

घर में अवैध रूप से प्रतिबंधित लकड़ियों का भंडारण, हुई कार्रवाई

■ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इमारती लकड़ियों का जखीरा बरामद किया, टीम को लकड़ी काटने की मशीन भी मिली

जीपीएम। जिले के मरवाही वनमंडल में अवैध लकड़ी कारोबार के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम पिपरखुटी गांव में भारी मात्रा में साल लकड़ी जब्त की गई है। यह कार्रवाई मरवाही वनमंडल अधिकारी ग्रीष्मी चाँद के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम पिपरखुटी के कक्ष क्रमांक 2324 एवं 2325 क्षेत्र में अवैध रूप से साल लकड़ी का भंडारण किया गया है। सूचना मिलते ही डीएफओ के निर्देश पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमार कार्रवाई शुरू की।

जांच के दौरान लाल सिंह राठौर के घर से 136 नग साल चीरान और 11 नग साल के लठ्ठे बरामद किए गए। वन विभाग ने सभी लकड़ियों को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई देर शाम शुरू हुई और रात लगभग 10 बजे तक चलती रही। भारी मात्रा में साल लकड़ी मिलने के बाद ग्रामीणों के बीच चर्चा का माहौल बना हुआ है। वन विभाग इस मामले को गंभीर वन अपराध मानते हुए आगे की जांच में जुट गया है। कार्रवाई के दौरान आरोपी के घर से टीम को हाथ और मशीन से लकड़ी काटने वाले आरा भी मिले है सभी को जब्त कर लिया गया है साथ ही जब्त लकड़ी की कीमत का भी आंकलन किया जा रहा है। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन संपदा की सुरक्षा के लिए इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

स्कूल परिसर और खेल मैदान भी बने नशेड़ियों का अड्डा

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में नशे का कारोबार फैलता जा रहा है। शहर के सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, खेल मैदानों और यहां तक कि स्कूल परिसरों में भी खुलेआम नशा किए जाने के मामले सामने आने लगे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई इलाकों में नशीले इंजेक्शन, शराब की खाली बोतलें और अन्य आपत्तिजनक सामग्री खुले में बिखरी दिखाई दे रही है। नशे की आपत्तिजनक सामग्री जगह-जगह दिखने से आम लोगों में डर और नाराजगी बढ़ रही हैं। शाम होते ही कई सार्वजनिक स्थानों पर युवाओं का जमावड़ा लगने लगता है, जहां खुलेआम शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है। इसका असर अब सामाजिक माहौल पर भी साफ दिखाई देने लगा है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को इन क्षेत्रों से गुजरने में असहजता महसूस हो रही है। सबसे गंभीर स्थिति शहर के शैक्षणिक परिसरों और खेल मैदानों की बताई जा रही है। हाईस्कूल के खेल मैदान में चारों ओर शराब की खाली बोतलें और नशे से जुड़ी सामग्री पड़ी मिली है। जिस मैदान में विद्यार्थी खेलकूद और अभ्यास करने पहुंचते हैं, वहीं अब नशेड़ियों का जमावड़ा लगने लगा है। इससे खिलाड़ियों और छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर पुलिस प्रशासन का कहना है कि नशीले पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे मामलों में कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी विवेक पाटले ने बताया कि पुलिस द्वारा संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

लावारिस खड़े ट्रक से 19 भैंस बरामद, अंतर्राज्यीय तस्करी की आशंका

आरंग। आरंग पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ग्राम गुल्लू और गुदगुदा के बीच संदिग्ध अवस्था में खड़े एक मालवाहक वाहन से 19 भैंस बरामद की हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन मवेशियों को अवैध रूप से तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। जानकारी के अनुसार, आरंग पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गुल्लू और गुदगुदा के मध्य मुख्य मार्ग पर एक मालवाहक गाड़ी (क्रमांक UP 83 CT 8790) काफी देर से संदिग्ध परिस्थितियों में खड़ी है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। जब पुलिस टीम ने घेराबंदी कर वाहन की तलाशी ली, तो गाड़ी के पास या अंदर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। बताया जाता है कि पुलिस के आने की भनक लगते ही चालक और उसके साथी वाहन छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस दंग रह गई। मालवाहक के भीतर बेहद क्रूरता के साथ 19 भैंस ठूस-ठूस कर बांधी गई थीं। पुलिस ने तत्काल सभी मवेशियों को वाहन से बाहर निकाला।

अपॉइंटमेंट लेटर लेकर कलेक्टोरेट पहुंची युवती उड़े होश

रायगढ़। रायगढ़ जिले में कलेक्ट्रोरेट सारंगढ़ में कम्प्यूटर ऑपरेटर की नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रूपये की ठगी करने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने जशपुर से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आरोपी ने पीड़िता को संविदा नियुक्ति का झांसा देते हुए नगदी रकम समेत ऑनलाईन के माध्यम से रकम लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर फरार हो गया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम कोतरा निवासी कुमारी पदिमनी यादव (27 साल) ने 03 अप्रैल को कोतरारोड़ थाना में लिखित शिकायत देकर बताया कि कलेक्ट्रोरेट सारंगढ़ में कम्प्यूटर ऑपरेटर पद पर संविदा नियुक्ति कराने का भरोसा बीच कुल 3 लाख 38 हजार 500 रूपये नगद और फोन-पे के माध्यम से प्राप्त कर लिया था। लंबे समय तक नियुक्ति नही हुई तो आरोपी लगातार आज-कल कहकर टालमटोल करता रहा। इस दौरान पीड़िता को कॉल मी सर्विसेस नामक संस्था का एक नियुक्ति पत्र दिया गया जिसे लेकर जब वह कलेक्ट्रोरेट रायगढ़ पहुंची तो जांच में दस्तावेज पूरी तरह फर्जी पाया गया।

पंचायत भवन पर डीजल डालकर लगा दी आग

जगदलपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के बोरपदर में एक युवक ने पंचायत भवन और अपने ट्रैक्टर में आग लगा दी। यह घटना पंचायत से काम का भुगतान न मिलने के कारण गुस्से में आकर की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि बोरपदर निवासी अजय गोयल (36 वर्ष) ने कुछ महीने पहले पंचायत की ओर से निकले काम को पूरा किया था। काम पूरा करने के लिए उसने एक ट्रैक्टर भी खरीदा था। काम पूर्ण होने के बाद भुगतान की बात भी हुई थी। हालांकि, सरपंच की ओर से लगातार कहने के बाद भी भुगतान नहीं हो पा रहा था। इससे अजय गोयल काफी गुस्से में था। बीती रात वह डीजल लेकर पंचायत भवन पहुंचा। उसने भवन के अंदर डीजल डालकर आग लगा दी। इस घटना में भवन के अंदर रखी कुर्सियां और दीवार पर लगे कुछ फोटो जल गए। ग्रामीणों ने आग देखकर पुलिस को सूचना दी और पानी डालकर आग बुझाई। इस घटना से पहले युवक अजय गोयल ने अपने ट्रैक्टर को भी आग के हवाले कर दिया था।

ट्रक लेकर प्लांट नहीं पहुंचा ड्राइवर, तलाश जारी

रायगढ़। रायगढ़ जिले में एक ट्रक चालक ने अमानत में खयानत की है। कोयला लेकर संयंत्र जाने निकले चालक ने 24.620 मीट्रिक टन कोयला कहीं और बेच दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। यह मामला घरघोड़ा थाना क्षेत्र का है। विवेक पाण्डेय ने घरघोड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जनवरी माह में विवेक के नाम पर जामपाली कोयला खदान में डी.ओ. संख्या 72728 आवंटित था। इसके तहत जामपाली खुली खदान से आर.एस. मेटा संयंत्र अकलतरा तक कोयला जाता था। 27 जनवरी को विवेक ने जामपाली खदान के प्रवेश द्वार पर डालाबॉडी ट्रक (क्र. सीजी-12 एस-4455) खड़ा देखा। चालक ने अपना नाम लल्लन यादव निवासी झारखंड बताया। लल्लन यादव ने खुद को वाहन का मालिक बताते हुए मोबाइल संख्या दी। विवेक ने आर.एस. मेटा संयंत्र अकलतरा के लिए 700 रुपये प्रति टन भाड़ा तय किया। शाम 24.620 मीट्रिक टन जी-10 श्रेणी का कोयला ट्रक में लोड कराया गया।

बहन के घर जाने निकली महिला 3 बच्चों सहित लापता

तखतपुर। क्षेत्र के ग्राम सावाडबरा से एक महिला अपने तीन नाबालिग बच्चों सहित रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई है। घटना के पांच दिन बीत जाने के बाद भी महिला और बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलने से परिजनों की चिंता बढ़ गई है, वहीं पूरे इलाके में मामले को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।जानकारी के अनुसार, महिला बीते 4 मई को अपने तीन बच्चों के साथ बहन के घर बिलासपुर जाने की बात कहकर घर से निकली थी। इसके बाद से उसका मोबाइल बंद आ रहा है और परिवार का उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। परिजनों ने पहले अपने स्तर पर तलाश की, लेकिन जब कहीं कोई जानकारी नहीं मिली तो मामले की सूचना तखतपुर थाना में दी गई।मामले में पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि पांच दिन गुजर जाने के बाद भी महिला और बच्चों का कोई पता नहीं चलने से परिजनों के साथ-साथ समाज के लोगों में भी नाराजगी बढ़ती जा रही है।

तेंदूपत्ता तोड़ने वाला लड़का बना आईएफएस अफसर, देशभर में हासिल की 91वीं रैंक

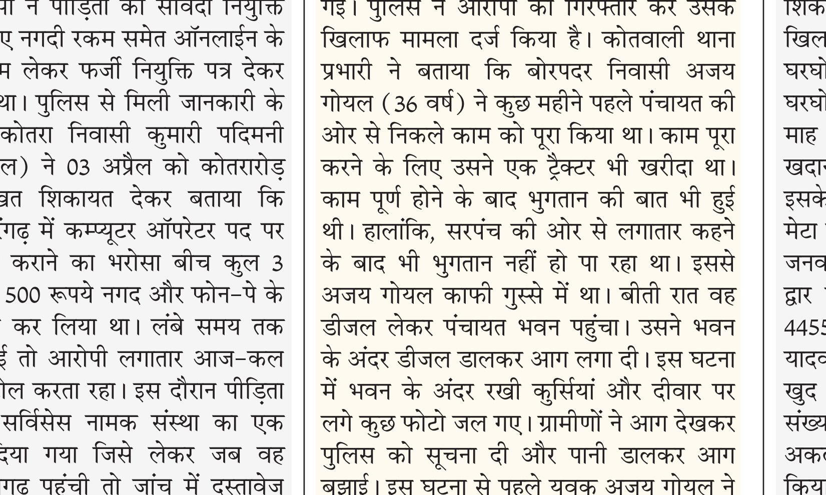

रायगढ़। सुबह की पहली किरण जैसे ही रायगढ़ जिले के संबलपुरी गांव की पगडंडियों पर उतरती थी, एक परिवार जंगल की ओर निकल पड़ता था। उस परिवार के साथ एक दुबला-पतला लड़का भी चलता जो कभी तेंदूपत्ता तोड़ता, कभी महुआ बीनता। उसे तब शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन यही जंगल उसकी पहचान बन जाएगा। उस लड़के का नाम था, अजय गुप्ता। आज वही अजय गुप्ता भारतीय वन सेवा ([illegible]) परीक्षा में पूरे देश में 91वीं रैंक हासिल कर चुका है। जिस जंगल से कभी उसके परिवार का चूल्हा जलता था, अब उसी जंगल की हिफाज़त की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आने वाली है। यह सिर्फ अजय गुप्ता की सफलता की कहानी नहीं है। यह कहानी ग्रामीण अंचलों के कच्ची मिट्टी के घर में बसते संघर्ष की है, जहां तमाम अभावों के बाद भी सपने जिंदा रहते हैं। अजय गुप्ता का बचपन बेहद कठिन परिस्थितियों में बीता। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि बड़े सपने देखे जा सके। घर कच्ची मिट्टी और खपरैल का था। छत के बीच से आती धूप की किरणें जिंदगी में कभी-कभी उम्मीद की रोशनी भर देती थी। परिवार साल के छह महीने खेती करता और गर्मी के मौसम में जंगलों से तेंदूपत्ता तोड़कर गुजारा करता था। दो जून की रोटी जुटाने के लिए पूरे परिवार को हाड़तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। गर्मी की छुट्टी के दिनों सुबह होते ही अजय भी अपने माता-पिता के साथ जंगल निकल जाते थे। अजय का बचपन तेंदूपत्ता तोड़ने, महुआ बीनने और खेती किसानी के मौसम में खेतों में काम करते हुए बीतता। इस संघर्षों के बीच भी उनके माता-पिता ने एक सपना कभी मरने नहीं दिया। वह सपना था, अपने बच्चों की पढ़ाई का।माता-पिता निरक्षर थे, मगर शिक्षा की ताकत को समझते थे। जिंदगी भर जो कमाया, उससे परिवार का पेट भी भरा और बच्चों की पढ़ाई भी चलती रही।

अजय पढ़ाई में शुरू से ही बेहद मेधावी रहे। साल 2011 में उन्होंने 10वीं कक्षा में 93 प्रतिशत अंक हासिल किए। यह उनके जीवन का बड़ा मोड़ साबित हुआ। तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के बच्चों के लिए सरकार ने छात्रवृत्ति योजना शुरू की थी। अजय को इस योजना का लाभ मिला और आगे की पढ़ाई का रास्ता आसान हुआ। उन्होंने 12वीं कक्षा में भी शानदार प्रदर्शन किया और इसके बाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर में प्रवेश मिला। एनआईटी में पढ़ाई के दौरान भी उन्हें तीन वर्षों तक छात्रवृत्ति मिलती रही।अजय कहते है- पहले सपने बहुत बड़े नहीं थे। लगता था कि हमारी दुनिया बस गांव तक सीमित है, लेकिन एनआईटी में एडमिशन लेने के बाद नजरिया बदल गया। पहली बार लगा कि मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं। एनआईटी में पढ़ाई के दौरान ही अजय को कैंपस प्लेसमेंट मिला। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह बस्तर में काम कर रही संस्था 'प्रदान' से जुड़ गए। यहां उन्होंने आदिवासी समुदायों के बीच चार वर्षों तक काम किया। लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में काम करते हुए उन्होंने आदिवासियों के जीवन और जंगल के रिश्ते को बेहद करीब से समझा। बस्तर के अनुभवों ने उनके भीतर समाज और प्रकृति के लिए कुछ बड़ा करने की इच्छा को और मजबूत किया।साल 2021 में अजय ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और [illegible] की तैयारी शुरू कर दी। यह रास्ता आसान नहीं था। उन्होंने चार बार मेन्स परीक्षा लिखी और तीन बार इंटरव्यू तक पहुंचे। हर बार मंज़िल सामने दिखती, लेकिन सफलता हाथ से फिसल जाती, लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। क्योंकि संघर्ष उनके जीवन का हिस्सा पहले से था। साल 2025 अजय गुप्ता की जिंदगी में नई करवट लेकर आया। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया 452वीं रैंक हासिल की और भारतीय राजस्व सेवा के लिए चयनित हुए। परिवार और गांव में खुशी का माहौल था, लेकिन इसके तुरंत बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्विस परीक्षा का परिणाम भी आया। देशभर में 91वीं रैंक मिली। अब उनके सामने दो रास्ते थे, [illegible] या [illegible], लेकिन अजय के लिए फैसला मुश्किल नहीं था। उन्होंने भारतीय राजस्व सेवा की बजाय भारतीय वन सेवा को चुना। क्योंकि जंगल उनके लिए सिर्फ पेड़ नहीं थे, जिंदगी थे। अजय कहते हैं कि जंगल उनके बचपन से ही जिंदगी का हिस्सा रहा है। जंगल ने उन्हें सिर्फ रोजगार नहीं दिया, बल्कि जीवन की दिशा भी दी। वह कहते हैं, बचपन से मेरा जुड़ाव जंगल से रहा है।

संक्षिप्त समाचार

12-13 मई को आयोजित होगी छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा कार्यसमिति

की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक राजधानी रायपुर में 12 और 13 मई को आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी, जिला अध्यक्ष, कोर ग्रुप की बैठक होगी। इसकी जानकारी वन मंत्री केदार कश्यप ने दी है। वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इस बैठक में संगठन के मंडल जिला प्रशिक्षण वर्ग की समीक्षा के साथ ही आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय की जाएगी। वहीं उन्होंने आगे बताया कि पार्टी इसमें एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित करेगी, जिसमें बंगाल, असम चुनाव में भाजपा की जीत पर मतदाताओं के साथ पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया जाएगा।

रायपुर में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम खेलेगी 3 मैच

रायपुर। राजधानी रायपुर के शहीद वीर

नारायण सिंह स्टेडियम में इस साल सिर्फ आईपीएल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल टी-20 मैचों का तड़का भी लगने वाला है। बीसीसीआई ने आगमी सीजन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। भारतीय सीनियर महिला टीम अक्टूबर महीने में जिम्बाब्वे महिला टीम की मेजबानी करते नजर आने वाली हैं। यह दोनों देशों के बीच पहली द्विपक्षीय सीरीज होगी, जिसमें 6 सफेद गेंद के मुकाबले खेले जाएंगे। रायपुर में 16 अक्टूबर को पहला टी20, 18 अक्टूबर को दूसरा टी20, 20 अक्टूबर को तीसरा टी20 खेले जाएंगे। जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम का यह ऐतिहासिक दौरा होने वाले है, क्योंकि यह उनका पहला भारत दौरा होगा। दोनों देशों की महिला टीमें पहली बार द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेलेंगी। इससे पहले दोनों टीमों के बीच मुकाबले केवल आईसीसी टूर्नामेंट और क्वालिफायर प्रतियोगिताओं तक सीमित रहे हैं। भारतीय महिला टीम ने भी अब तक जिम्बाब्वे का दौरा नहीं किया है। आगामी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के मद्देनजर बीसीसीआई महिला क्रिकेट के द्विपक्षीय सीरीज बढ़ा रही है। दरअसल वर्ष 2027 में श्रीलंका में महिला टी20 चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। ऐसे में यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

बलौदा बाजार कलेक्टर ने प्रगणक बन किया डिजिटल जनगणना

रायपुर। भारत सरकार जनगणना कार्य निदेशालय के निर्देशानुसार जनगणना 2026 के प्रथम चरण अंतर्गत बलौदाबाजार जिले में 1 मई से मकान सूचीकरण और गणना कार्य संचालित है। प्रगणक घर- घर जाकर डिजिटल गणना कर रहे हैं। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने शनिवार को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनगणना कार्य का अवलोकन किया। उन्होंने ग्राम मुण्डा में प्रगणको द्वारा किये जा रहे जनगणना कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रगणक से मोबाइल लेकर स्वयं एक मकान मालिक के घर पहुंचे और मकान गणना सबंधित सभी जानकारी लेकर डिजिटल गणना पूरा किया। कलेक्टर श्री शर्मा ने मकान मालिक कार्तिक राम साहु को बताया कि भारत सरकार जनगणना निदेशालय के निर्देशानुसार पूरे देश में जानगाना का कार्य चल रहा हैं. इसमें प्रथम चरण में मकानों क़ी गणना क़ी जा रही हैं जिसमें प्रगणक घर- घर जाकर जानकारी अवश्यक जानकारी लेकर डिजिटल गणना पूरा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो भी जानकारी प्रगणको को बेझिझक दें, यह पूरी तरह गोपनीय रहेगा। आधार कार्ड, पेन कार्ड या कोई ओटीपी क़ी जरुरत नहीं है। उन्होंने प्रागणको से गणना कार्य के सम्बन्ध में पूछ ताछ। प्रगणको ने बताया कि उनके एचएलबी में 348 मकानों क़ी गणना हो गई हैं।

एकलव्य विद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाईन प्रशिक्षण का आयोजन

रायपुर। आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा के निर्देशानुसार एकलव्य विद्यालयों में प्रवेश से संबंधित ऑनलाइन काउंसिलिंग हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आदिम जाति विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में संचालित 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षण सत्र 2026-27 में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया के संबंध में गुरूवार, 07 मई को आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर के सभाकक्ष में प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में सभी 26 जिलों में संचालित 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के प्राचार्य प्रवेश प्रभारी शिक्षक एवं जिला कार्यालयों में पदस्थ प्रभारी लिपिकों को ऑनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया से संबन्धित विभिन्न चरणों का विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

टाटा एआईजी ने छत्तीसगढ़ में एमएसएमई जोखिम सुरक्षा को किया मज़बूत

8,500 से अधिक पॉलिसियों के साथ दर्ज की शानदार वृद्धि

- **टाटा एआईजी ने भारत में एमएसएमई क्षेत्र में 1400 करोड़ के प्रीमियम का आंकड़ा पार किया; छत्तीसगढ़ प्रमुख उभरते बाज़ारों में शामिल**

रायपुर। भारत की एक अग्रणी जनरल इन्शुरन्स कंपनी, टाटा एआईजी जनरल इन्शुरन्स कंपनी ने छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कमर कस ली है। रायपुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर और दुर्ग जैसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, छत्तीसगढ़ के एमएसएमई क्षेत्र के लिए जोखिम सुरक्षा को मज़बूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।

छत्तीसगढ़ में एमएसएमई क्षेत्र का तेज़ी से विस्तार हुआ है; यहाँ एग्री-स्टोरेज इकाइयों, राइस मिलों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे विविध क्षेत्रों में करीब 13.5 लाख उद्यम मौजूद हैं। इसी आर्थिक प्रगति का परिणाम है कि राज्य में अब जीएसटी करदाताओं की संख्या 1.5 लाख के आंकड़े को छू रही है।

टाटा एआईजी ने छत्तीसगढ़ में 8,500 से अधिक एसएमई पॉलिसियां जारी की हैं, जिसमें पिछले वर्ष 25त्न से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी ने वित्त वर्ष 26 में भारत के एमएसएमई क्षेत्र में ?1,400 करोड़ के प्रीमियम का ऐतिहासिक पड़ाव पार कर लिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरा है।

इस विकास को और गति देने के लिए, टाटा एआईजी ने वित्त वर्ष 26 में छत्तीसगढ़ में एक डेडिकेटेड ज़ोन स्थापित कर अपनी उपस्थिति मज़बूत की है, जिसे विशेष एसएमई अंडरराइटर्स और क्लेम प्रोफेशनल्स ने समर्थन दिया है। इस निवेश का उद्देश्य क्षेत्र के व्यवसायों के लिए त्वरित जोखिम मूल्यांकन, कस्टमाइज्ड कवरेज समाधान और कुशल क्लेम सेवाएं सुनिश्चित करना है। वित्त वर्ष 26 में, कंपनी ने भारत में 7.5 लाख से अधिक एमएसएमई पॉलिसियां जारी कीं और अपने कमर्शियल पोर्टफोलियो के तहत ग्रुप हेल्थ, ग्रुप एक्सीडेंट और कर्मचारी कम्पेन्सेशन पॉलिसियों के माध्यम से 20 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षा प्रदान की।छत्तीसगढ़ में बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जलवायु परिवर्तन और इलाज के बढ़ते खर्चों की वजह से आग लगने और कर्मचारियों की सेहत से जुड़े जोखिम बढ़ गए हैं। इन खतरों को देखते हुए अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग और कंपनियां इंश्योरेंस का सहारा ले रही हैं।

विस्तार पर टिप्पणी करते हुए, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस के हेड -एमएसएमई प्रोडक्ट्स, श्री प्रणय शाह ने कहा- भारत की एमएसएमई विकास यात्रा में छत्तीसगढ़ की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारा ध्यान राज्य के उद्यमों के बदलते जोखिमों को समझने और उन्हें भरोसेमंद व सुलभ बीमा समाधान प्रदान करने पर है। वित्त वर्ष 26 में, हमने प्रमुख क्षेत्रों में भारी वृद्धि देखी है, जिसमें फायर इंश्योरेंस और कन्स्ट्रक्शन इंश्योरेंस में 30त्न से अधिक और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में 20त्न से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। स्थानीय स्तर पर अपनी उपस्थिति को मज़बूत करके और विशेषज्ञ क्षमताओं में निवेश करके, हमारा लक्ष्य एमएसएमई को सशक्त बनाना, आजीविका की रक्षा करना और व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करना है।

छत्तीसगढ़ में बढ़ते एमएसएमई क्षेत्र के साथ कदम मिलाते हुए, टाटा एआईजी व्यवसायों को उनकी उभरती आवश्यकताओं के अनुसार सटीक बीमा सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी स्थानीय समझ, आधुनिक तकनीक और ग्राहक केंद्रित सेवाओं के दम पर, कंपनी इन उद्यमों को मज़बूत बनाने और उनके विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद कर रही है।

जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन

मंत्री टंकराम वर्मा ने किया विभागीय स्टालों का अवलोकन

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने के संकल्प के साथ सरसीवा तहसील के ग्राम पंचायत झुमका में 'सुशासन तिहार' के अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में प्रदेश के राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा शामिल हुए।

मंत्री वर्मा ने शिविर में विभागीय स्टालों का अवलोकन कर आवेदन निराकरण की स्थिति जानी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हितग्राहियों को ट्रैक्टर की चाबी, अनुदान राशि के चेक, प्रमाण पत्र और अन्य सामग्री भेंट कर उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए।

इस शिविर में कुल 2310 आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमे से 272 का तत्काल निराकरण किया गया। एक कृषक हितग्राही को ट्रैक्टर खरीदी पर 2.50 लाख रुपये का अनुदान और कई किसानों को बोर खनन हेतु 43 हजार रुपये के चेक वितरित किये गए। इसी तरह नन्हे बच्चों का अन्नप्राशन, गर्भवती महिलाओं को उपहार और आयुष्मान कार्ड का भी वितरण किया गया।

ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार 'अंत्योदय' के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हर पात्र हितग्राही को उनका हक मिलेगा, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि शिविर में प्राप्त एक-एक आवेदन का निराकरण समय-सीमा के भीतर हो।

शिविर में प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए विभिन्न विभागों के माध्यम से बड़ी संख्या में लाभान्वित किया गया। शिविर में किसान पुस्तिका, बी-1 और विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसी तरह मत्स्य एवं खाद्य विभाग द्वारा मछुआरों को जाल और पात्र परिवारों को नए राशन कार्ड सौंपे गए। दिव्यांग प्रमाण पत्र, पेंशन स्वीकृति और प्रधानमंत्री आवास के पूर्णता प्रमाण पत्र बांटने के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद विभाग द्वारा शिविर लगाकर ग्रामीणों का नि:शुल्क परीक्षण किया गया।

कार्यक्रम में बिलाईगढ़ विधायक कविता लहरे,जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पांडेय,और ग्राम पंचायत झुमका के सरपंच धनंजय साहू, कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में जुटे ग्रामीणों ने शासन की इस पहल की सराहना करते हुए विभिन्न योजनाओं के लिए अपना पंजीयन कराया।

सुशासन तिहार : आमजन की समस्याओं का हो रहा निराकरण

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेशभर में आयोजित सुशासन तिहार 2026 के तहत आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही पात्र हितग्राहियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मौके पर प्रदान किया जा रहा है।

इसी क्रम में जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड के ग्राम सिमड़ा में आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में 4 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवासों की चाबी सौंपी गई।

लाभान्वित हितग्राहियों में ग्राम सिमड़ा की जेरोम, मयूरचुंदी के बीरबल यादव, करडेगा के टूना राम तथा जगदीश यादव शामिल हैं। पक्के मकान की चाबी पाकर सभी हितग्राहियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब उन्हें बारिश, धूप और अन्य कठिनाइयों से राहत मिलेगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उनका सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का सपना साकार हुआ है और अब वे अपने परिवार के साथ नए घर में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। सुशासन तिहार के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आयोजित सुशासन तिहार 2026 आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है। गांव-गांव, द्वार-द्वार पहुंच रही प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का निराकरण कर उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ भी प्रदान

किया जा रहा है।

इसी क्रम में जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड के ग्राम सिमड़ा में आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में पात्र हितग्राहियों को राशन कार्ड वितरित किए गए। शिविर में कुल 5 हितग्राहियों को नए राशन कार्ड प्रदान किए गए, जिससे उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। लाभान्वित हितग्राहियों में ग्राम सिमड़ा की अनामिका टोप्पो, मयूरचुंदी की लीलावती गोंड तथा सेली खेस की गीता सिंह सहित अन्य हितग्राही शामिल हैं। राशन कार्ड प्राप्त होने पर महिलाओं ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया। हितग्राहियों ने कहा कि सुशासन तिहार उनके लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुआ है। अब उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि प्रशासन स्वयं गांव के नजदीक पहुंचकर त्वरित समाधान उपलब्ध करा रहा है।सुशासन तिहार के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है, जिससे आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।

16 मई को जामटोली और कुनकुरी में लगेंगे जनसमस्या निवारण शिविर

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जशपुर जिले में सुशासन तिहार 2026 के तहत जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों में जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 16 मई 2026 को जशपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम जामटोली तथा नगर पंचायत कुनकुरी में शिविर आयोजित किए जाएंगे। जामटोली में आयोजित शिविर में जामटोली, बड़ाबनाई, जुरतेला, पुत्रीचौरा, पिलखी, साईटांगरटोली, पोड़ी, लोदाम, बाम्हनपुरा, चौलीटांगरटोली, पोरतेंगा, झोलंगा, जकबा और लोखण्डी सहित 14 गांवों के ग्रामीण अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। इसी प्रकार नगर पंचायत कुनकुरी के वार्ड क्रमांक 1 से 15 तक के नागरिक भी शिविर में भाग लेकर अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि कुनकुरी नगरीय निकाय का यह शिविर पूर्व में 11 मई 2026 को प्रस्तावित था, जिसे संशोधित कर अब 16 मई 2026 को आयोजित किया जाएगा। सुशासन तिहार के अंतर्गत नागरिकों से प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। यह अभियान प्रशासन को आमजन के और अधिक निकट लाने तथा उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बन रहा है। जशपुर कलेक्टर ने शिविरों के सफल संचालन के लिए नोडल एवं विभागीय अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के संबंधित शिविर में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि उनकी समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

कांग्रेस में एकता नहीं, इनके बीच आपस में लड़ाई : मिश्रा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है, जिसको लेकर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दीपक बैज का कार्यकाल जुलाई में पूरा हो रहा है और कार्यकारिणी तक नहीं बना पाए।

वहीं उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस में एकता नहीं है, आपस में इनके बीच लड़ाई है। 3200 करोड़ का घोटाला हुआ था उसका बटवारा नहीं होने से आपस में कॉम्पिटीशन है। दीपक बैज का कार्यकाल जुलाई में पूरा हो रहा है और कार्यकारिणी तक नहीं बना पाए। टीएस सिंहदेव कहते हैं मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूं, अमरजीत कहते हैं मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूं, दीपक बैज चाहते हैं कि मैं अध्यक्ष बना रहूं। मैं कहता हूं कि आपस में तय कर लो जनता को कंफ्यूज मत करो। वैसे भी आपका भारत से कांग्रेस मुक्त होना तय है हमारे पार्टी का एजेंडा है कि भारत कांग्रेस से मुक्त हो और सनातन का राज चले। पश्चिम बंगाल, असम में यह भी बता दिया कि कांग्रेस की कोई औकात नहीं है।

भाजपा का फोकस बिलासपुर की सीटों पर है। इस मामले में विधायक पुरंदर मिश्रा का कहना है कि भाजपा कहीं कमजोर नहीं है। छत्तीसगढ़ से लेकर बंगाल तक बीजेपी की सरकार है। आज बंगाल में नए मुख्यमंत्री का शपथ हो रहा है। भाजपा ने भारत को पाकिस्तान बनने से बचाया है

मुख्यमंत्री निवास घेराव के दौरान शासकीय कार्य में बाधा का आरोप

एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज

रायपुर। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने वाले एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अज्ञात कार्यकर्ताओं पर सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी। आरोप है कि लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला किया गया, जिसमें करीब 10 पुलिसकर्मी घायल हुए। शासकीय कार्य में बाधा, शासकीय कर्मचारियों पर हमला समेत अन्य धाराओं के तहत एफआईआर कायम की गई है।

दरअसल, बुधवार को प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर राजधानी रायपुर में बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले थे। प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय के नेतृत्व में प्रदेशभर से पहुंचे सैकड़ों छात्र-युवा कार्यकर्ताओं ने बूढ़ापारा से रैली निकालकर सीएम हाउस की ओर कूच किया। इस दौरान बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली थी। कार्यक्रम में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ शामिल होने पहुंचे थे।

कार्यक्रम में कांग्रेस नेता और विधायक देवेन्द्र यादव, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, पूर्व महापौर एज़ाज ढेबर, युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा, पूर्व विधायक गुलाब कामरो, संजीव शुक्ला, पंकज मिश्रा, सुबोध हरितवाल, निखिल कांत साहू, अजीत कुकरेजा, भावेश शुक्ला, अमित शर्मा, हेमंत पाल, शांतनु झा, प्रशांत गोस्वामी समेत प्रदेशभर से एनएसयूआई पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

जानकारी के मुताबिक, एनएसयूआई के सीएम हाउस घेराव के दौरान लाठी,डंडे समेत पथराव किया गया, जिसपर पुलिस ने एक्शन लिया गया है। बताया जा रहा है कि हमले में पुलिसकर्मी मोहन ध्रुव,माडवी बुधरा,रमेश कुडियाम,जैनेन्द्र कुमार नाग, भोलेन्द्र ठाकुर, सोमा मडकाम,रामसिंह कवाची, उन्दाम राजू,अनिल भारती और सोयम मुकेश घायल हुए थे। मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

वेदांता पावर प्लांट हादसा पर सियासत

युवा कांग्रेस ने पीसी कर जारी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, लगाए कई गंभीर आरोप

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में हुए वेदांता पावर प्लांट हादसे पर सियासत तेज हो गई है। युवा कांग्रेस ने आज फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होने प्लांट के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और पूरे प्रदेश के पावर प्लांट का सेफ्टी ऑडिट कराने की मांग की है।

युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और कुनकुरी नगर पालिका अध्यक्ष विनयशील गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि हादसे की जांच में चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। पावर प्लांट के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती गई और मामले की एफआईआर आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई।

वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले को रफा दफा करने की कार्रवाई चल रही है। हादसे के 10 दिन पहले प्लांट में शॉर्ट शटडाउन हुआ था। शॉर्ट शटडाउन के बाद उद्योग विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है, तो क्या परमिशन ली गई थी?

इसी के साथ ही उन्होंने मांग की है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी पॉवर प्लांट है उनकी सेफ्टी ऑडिट कराई जाए। वहीं उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मुआवजा देकर ही मामला खत्म कर दिया जाएगा? अगर एफआईआर सार्वजनिक नहीं की जाएगी और कड़ी धाराएं नहीं लगाई गई, तो युवा कांग्रेस सक्ति जिले से रायपुर तक प्रदर्शन करेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग, कार्यालय वन मंडलाधिकारी, बस्तर, वन मंडल, जगदलपुर

// संक्षिप्त निविदा सूचना आमंत्रण //

सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कैम्पा शासकीय स्ट्राईक फोर्स एवं अंतिम रूप से राजसातकृत वाहनों को निविदा द्वारा निवर्तित किया जाना है। इस बाबत निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत शर्तें तथा वाहनों की सूची कार्यालयीन दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है एवं निविदा प्रपत्र हेतु राशि रू. 200/- का मनी रसीद परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर (सा.) से प्राप्त कर निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत शर्तें इस कार्यालय से प्राप्त कर निविदा फार्म जमा करने की निर्धारित तिथि एवं समय में इस कार्यालय में बंद लिफाफा के साथ जमा कर सकते है।

प्रथम निविदा में वाहन के विक्रय दर से प्राप्त मूल्य अवरोध मूल्य से कम तथा अधिक एवं शासकीय हित मे नहीं होने पर द्वितीय एवं तृतीय चक्र की निविदा नीचे दर्शित तिथि को आमंत्रित की जाती है।

क्र.	विवरण	प्रथम निविदा की तिथि एवं समय सारणी	द्वितीय निविदा की तिथि एवं समया सारणी	तृतीय निविदा की तिथि एवं समय सारणी
.1	निविदा फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि	दिनांक 15.06.2026 सांयकाल 05.00 बजे तक	दिनांक 07.07.2026 सांयकाल 05.00 बजे तक	दिनांक 20.07.2026 सांयकाल 05.00 बजे तक
2	निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 16.06.2026 सांयकाल 02.00 बजे तक	दिनांक 08.07.2026 सांयकाल 02.00 बजे तक	दिनांक 21.07.2026 सांयकाल 02.00 बजे तक
3	3 निविदा खोले जाने की तिथि	दिनांक 16.06.2026 सांयकाल 03.00 बजे तक	दिनांक 08.07.2026 सांयकाल 03.00 बजे तक	दिनांक 21.07.2026 सांयकाल 03.00 बजे तक
4	4 निविदा खोले जाने का स्थान	कार्यालय वन मण्डलाधिकारी बस्तर वनमण्डल जगदलपुर	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी बस्तर वनमण्डलजगदलपुर	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी बस्तर वनमण्डल जगदलपुर

वन मण्डलाधिकारी
बस्तर वन मण्डल जगदलपुर

जी-262700604/4

संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ता विपक्ष

सुरेश हिंदुस्तानी

पश्चिम बंगाल के साथ पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के पश्चात् जो तस्वीर निर्मित हुई है, वह कड़वाहट और मिठास दोनों का ही स्वाद दे रही है। विपक्ष के राजनीतिक दल जहाँ एक ओर तमिलनाडु और केरल के मनमाफिक परिणाम देखकर मिठास का स्वाद ले रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम को सभी विपक्षी दल भाजपा की प्रायोजित जीत के रूप में प्रचारित करने का असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी को इस बार जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, लेकिन ममता बनर्जी कुर्सी से चिपके रहने के अंदाज में पराजय को स्वीकार करने का मानस नहीं बना पा रही हैं। लोकतान्त्रिक मर्यादा के तहत उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी का त्याग करना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी ऐसा न करके एक प्रकार से लोक के निर्णय को ठेंगा दिखाने का कार्य कर रही हैं। खास बात यह है कि विपक्ष के कुछ अन्य दल भी तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के इस कदम का समर्थन करती हुई लग रही हैं। लोकतंत्र में विरोध करने का सभी को अधिकार है, लेकिन यह विरोध संवैधानिक मर्यादायों के तहत ही होना चाहिए।

देश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है, ज़ब चुनाव में पराजित हो जाने के बाद मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देने से मना कर रहा है, ममता बनर्जी का यह रवैया निश्चित ही जनमत के साथ विश्वासघात ही कहा जाएगा। लोकतंत्र का असली आशय यही होता है कि जनता अपने बीच में से अपने प्रतिनिधि चुनकर अपनी सरकार बनाती है। जनता ने जनादेश दे दिया है। विपक्ष को भी यह स्वीकार करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम यह संदेश प्रवाहित कर रहे हैं कि अब देश में तुष्टिकरण के दिन ख़त्म हो गए हैं। जनता भी ऐसा ही चाहती है। मजेदार तथ्य यह है कि बंगाल के चुनाव के साथ ही पांच राज्य असम, केरल, तमिलनाडु और पंडिचेरी में भी चुनाव हुए असम को छोड़ दिया जाए तो सभी राज्यों में परिणाम सत्ता के विरोध में ही आए, लेकिन सवाल यह है कि इन राज्यों के परिणाम पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। इसके पीछे यही कारण माना जा रहा कि वहां भाजपा नहीं जीती। भाजपा की जीतना विपक्ष को कभी नहीं पचा। विपक्ष का व्यवहार ऐसा होता जा रहा है जैसे ये केवल सत्ता के लिए ही बने हैं। चुनाव में जय पराजय होती ही है, केवल एक को ही विजय मिलती है। पश्चिम बंगाल के बारे में यह सभी जानते हैं कि ममता सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था। जनता भी इस भ्रष्टाचार से त्रस्त रही और प्रशासनिक अधिकारी भी। इसी के चलते तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के विरोध में एक राजनीतिक हवा बनी। भाजपा ने अपने प्रचार के दौरान ममता के भ्रष्टाचार को लेकर जमकर हमला बोला। इसके विपरीत विपक्ष के अन्य दल भी इन मुद्दों पर मुखर रहे। कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से ममता को निशाने पर लिया। इसका आशय स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के विरोध में लहर थी। इसी कारण आम मतदाता बिना किसी भय के मतदान केंद्र तक पहुँचने में सफल हुआ। इसी ने भाजपा की राह आसान की। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि वहां की मतदाता सूची से फर्जी नाम विलोपित किए गए। इन नामों में कई तो ऐसे थे, जो इस दुनिया में नहीं हैं। हालांकि यह एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, इसलिए इसे खास मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रति वर्ष मतदाता सूची से नाम हटाने और जोड़ने का क्रम चलता है। बंगाल का मामला बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुडा था, इसलिए वहां एसआईआर जरुरी था।

बंगाल की हिंसा लोकतंत्र पर धब्बा और बड़ी चुनौती

ललित गर्ग

पश्चिम बंगाल में हाल ही में सम्पन्न विधानसभा चुनावों के बाद जिस प्रकार हिंसा, हत्याओं, आगजनी और राजनीतिक प्रतिशोध की घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने केवल राज्य की शांति को ही नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को भी आहत किया है। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव माना जाता है, किंतु जब यह उत्सव हिंसा, भय और प्रतिशोध में बदल जाए तो यह केवल राजनीतिक असफलता नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक पतन का संकेत बन जाता है। बंगाल की ताजा हिंसक घटनाएं इसी चिंता को सामने लाती हैं। चुनाव के दौरान छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो मतदान अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ था। लेकिन परिणामों की घोषणा के बाद जिस प्रकार राजनीतिक दलों के समर्थक एक-दूसरे के खिलाफ आक्रामक हुए, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अब वैचारिक संघर्ष न रहकर प्रतिशोध और वर्चस्व की लड़ाई बनती जा रही है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें, कई लोगों की हत्याएं और विशेष रूप से सुवेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ की हत्या ने पूरे घटनाक्रम को और अधिक गंभीर बना दिया। आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह क्यों बची रहनी चाहिए?

यह विडंबना है कि भारत, जिसने विश्व को अहिंसा, करुणा और वसुधैव कुटुम्बकम् का मंत्र दिया, आज वही देश राजनीतिक हिंसा के कारण अपनी छवि धूमिल करता दिखाई देता है। महात्मा गांधी ने राजनीति को नैतिकता और सेवा से जोड़ा था, लेकिन आज राजनीति सत्ता, प्रतिशोध और भय का माध्यम बनती जा रही है। बंगाल की हिंसा इस बीमारी का एक भयावह उदाहरण है। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास हिंसा से अछूता नहीं रहा है। वामपंथी शासन के लंबे दौर से लेकर तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल तक राजनीतिक संघर्ष कई बार रक्तरंजित रूप में सामने आया। बूथ कब्जाने, विरोधियों को डराने, स्थानीय दबंगों और अपराधी तत्वों का राजनीतिक संरक्षण-ये सब बंगाल की राजनीति की कटु वास्तविकताएं रही हैं। सत्ता बदलती रही, लेकिन राजनीतिक संस्कृति में अपेक्षित परिवर्तन नहीं आ सका। यही कारण है कि चुनाव

परिणामों के बाद भी हिंसा का वातावरण बनता है और आम नागरिक भय तथा असुरक्षा के बीच जीने को मजबूर होता है।

दरअसल जब राजनीति विचार और जनसेवा से हटकर केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम बन जाती है, तब हिंसा उसका स्वाभाविक परिणाम बनती है। हार को लोकतांत्रिक विनम्रता से स्वीकार करने के बजाय प्रतिशोध का माध्यम बना लेना लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है। यही कारण है कि चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देशों और विजय जुलूसों पर प्रतिबंध के बावजूद हिंसक घटनाएं हुईं। यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों की नैतिक विफलता भी है। ममता बनर्जी द्वारा चुनाव परिणामों पर सवाल उठाना और राजनीतिक टकराव को तीखा बनाना हो या भाजपा द्वारा आक्रामक राजनीतिक प्रतिक्रिया-दोनों पक्षों को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता दोनों की जिम्मेदारी होती है कि वे जनता को शांति और संयम का संदेश दें। दुर्भाग्य से हमारे राजनीतिक दल अक्सर कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नियंत्रित करने के बजाय उन्हें उकसाने का काम करते हैं। परिणामस्वरूप हिंसा सामान्य राजनीतिक व्यवहार का हिस्सा बनती जा रही है।

सबसे अधिक पीड़ा इस बात की है कि राजनीतिक हिंसा की कीमत हमेशा आम जनता को चुकानी पड़ती है। जिन लोगों के घर जलते हैं, जिन परिवारों के सदस्य मारे जाते हैं, जिन छोटे व्यापारियों की दुकानें टूटती हैं, उनका राजनीति से कोई सीधा संबंध नहीं होता। वे केवल उस हिंसक मानसिकता के शिकार बनते हैं जो सत्ता को मानवता से ऊपर मानती है। यह प्रश्न गंभीरता से पूछा जाना चाहिए कि आखिर राजनीतिक दल हिंसा का सहारा क्यों लेते हैं? जबकि इतिहास गवाह है कि हिंसा कभी स्थायी समाधान नहीं देती। हिंसा केवल भय, अविश्वास और प्रतिशोध को जन्म देती है। जो दल हिंसा को हथियार बनाते हैं, वे अंततः जनता की नजरों में अपना नैतिक अधिकार खो देते हैं। राजनीति का उद्देश्य समाज को जोड़ना होना चाहिए, तोड़ना नहीं।

आज भारत एक नए वैश्विक दौर में प्रवेश कर रहा है। दुनिया भारत को एक उभरती आर्थिक शक्ति, तकनीकी महाशक्ति और लोकतांत्रिक मॉडल के रूप में देख रही है। वर्ष 2047 तक जब भारत अपनी स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे करेगा, तब हमारा लक्ष्य केवल आर्थिक विकास नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसे सभ्य और नैतिक राष्ट्र का निर्माण भी होना चाहिए जहां राजनीति का आधार अहिंसा, संवाद और संवेदनशीलता हो। यदि राजनीतिक दल नफरत, सांप्रदायिकता और हिंसा को अपना हथियार बनाए रखेंगे, तो विकसित भारत का सपना अधूरा रह जाएगा। भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सांस्कृतिक चेतना रही है। गौतम बुद्ध ने करुणा का संदेश दिया, महावीर ने अहिंसा को जीवन का सर्वोच्च मूल्य बताया, गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर साम्राज्य को चुनौती दी। यह वही भारत है जिसने दुनिया को यह सिखाया कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और सह-अस्तित्व है। लेकिन आज राजनीतिक स्वार्थों और गैर-राजनीतिक आपराधिक तत्वों के कारण देश की छवि प्रभावित हो रही है। अपराधी मानसिकता के लोग राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। वे दल बदलते रहते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल शक्ति और स्वार्थ की पूर्ति होता है। बंगाल की ताजा घटनाओं में भी ऐसे तत्वों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता।

समाधान केवल प्रशासनिक कठोरता में नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तन में निहित है। सबसे पहले सभी राजनीतिक दलों को सार्वजनिक रूप से हिंसा की निंदा करनी चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं को संयम बरतने का स्पष्ट संदेश देना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को यह समझना होगा कि लोकतंत्र प्रतिद्वंद्विता का नहीं, सह-अस्तित्व का नाम है। दूसरा, कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। किसी भी दल से जुड़े उपद्रवियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखकर संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क निगरानी बढ़ानी होगी। तीसरा, राजनीति के अपराधीकरण पर कठोर नियंत्रण आवश्यक है। ऐसे लोगों को राजनीतिक दलों में प्रवेश ही न मिले जिनकी पृष्ठभूमि हिंसक और आपराधिक रही हो। राजनीतिक दलों को अपने भीतर नैतिक अनुशासन विकसित करना होगा। चैथा, समाज में लोकतांत्रिक शिक्षा और संवेदनशीलता का वातावरण बनाना होगा। विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं में संवाद, सहिष्णुता और अहिंसा के मूल्यों को मजबूत करना समय की आवश्यकता है। जब तक समाज स्वयं हिंसा को अस्वीकार नहीं करेगा, तब तक राजनीतिक हिंसा का अंत कठिन होगा।

बंगाल की ताजा हिंसा केवल एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के सामने खड़ी एक गंभीर चेतावनी है। यदि हमने समय रहते राजनीति को स्वस्थ मूल्यों की ओर नहीं मोड़ा, तो नफरत और हिंसा लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करती रहेंगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत अपनी आत्मा को पहचाने। यह देश युद्ध और प्रतिशोध की नहीं, बल्कि शांति, सह-अस्तित्व और विश्वबंधुत्व की भूमि है। वसुधैव कुटुम्बकम् केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत की सभ्यता का मूल दर्शन है। यदि राजनीति इस दर्शन से विमुख होगी, तो लोकतंत्र केवल सत्ता संघर्ष बनकर रह जाएगा। पश्चिम बंगाल को अब हिंसा और प्रतिशोध की राजनीति से बाहर निकलकर विकास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समरसता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यही लोकतंत्र की गरिमा है, यही जनता की अपेक्षा है और यही विकसित भारत का मार्ग भी।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

क्योंकि श्रात्मज्ञान मन और वृत्ति इन दोनों के पारस्परिक संघर्ष का परिणाम है अतः वह भरद्वाज कहा जाता है। उत्पन्न हुवे आत्मज्ञान का यमनियमादि साधनों द्वारा ही परिपोषण होता है, अतः यही भरद्वाज का देवताओं द्वारा रक्षित होने का अभिप्राय है। यही इस कथा का आध्यात्मिक भाव है। इतिहास पक्ष में वेदपुराणसमन्वयाध्याय के देवतावाद-प्रघट्टणित दिव्य चरित्रों का मनन करने से सब शंकाएं काफूर हो जायेंगीं। क्योंकि मनुष्ययोनि कर्मयोनि है अर्थात् इसमें किए गये शुभाशुभ कर्म भोगने पड़ते हैं और पशु पक्षी आदि तथा देव गन्धर्व आदि भोग-योनियें हैं इनमें पूर्व जन्मकृत अशुभ और शुभ कर्मों को केवल भोगना पड़ता है, अतः सूक्ष्म इच्छामय दिव्य शरीरधारी देवताओं के चरित्र स्थूल विकारी पाँच भोतिक शरीरधारी मनुष्यों के लिए अनुकरणीय नहीं होते। इसके अतिरिक्त जहाँ यह कथा आती है वहाँ पर इसे कहीं भी धर्मसंगत नहीं कहा है। ऐतिहासिक ग्रन्थों में बुरी भली सभी प्रकार की घटनायें लिखी रहती हैं। इससे सर्वसाधारण तादृश अनुकरण करने के लिए वाध्य हों सो बात नहीं है। हमारे विचार में यह कथा एक रूपकप्राय आख्यायिका है परन्तु वेदव्यास जी ने पुराणों की विशिष्ट शैली के अनुसार इसमें ऐतिहासिक अंश को भो विमिश्रित किया है, सो विश्लेषण करने पर इतना जान पड़ता है कि विनष्ट हुवे भरतकुल का उत्तराधिकारी भरद्वाज हुआ है ।

भाई बहिन का विवाह ?

कहा जाता है कि प्रसिद्ध राजा वेन के पुत्र राजा पृथु ने अपनी बहिन चि से विवाह किया था। हम इस आख्यान की बास्तविकता प्रकट करते हैं।

पौराणिक स्वरूप

अथ तस्य पुर्नावप्रैरपुत्रस्य महीपतेः।
बाहुभ्यां मथ्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत॥ 1।।

क्रमशः ...

मदर्स डे

इस दुनिया में जो सबसे अनमोल रिश्ता है वो है मां और बच्चे का। मां हमेशा अपने बच्चों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। मां का प्यार निस्वार्थ होता है। उसके प्यार में त्याग छिपा होता है। न जाने कितनी राते जगकर मां अपने बच्चों को पालकर बढ़ा करती है। जीवनभर प्यार करने के बाद भी उनका प्यार बच्चों के लिए बढ़ता ही रहता है। मां के लिए यूं तो हर दिन खास होता है लेकिन एक खास दिन उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका देती है। वो है मदर्स डे यानी मातृ दिवस। यह दिन हर साल सेलिब्रेट किया जाता है।

हर साल मई के दूसरे रविवार मदर्स डे मनाया जाता है। 2026 में 10 मई को यह दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। इस दिन बच्चे अपनी माताओं को गिफ्ट देकर उन्हें विश करते हैं। साथ ही उन्हें खास महसूस

करवाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं।

मदर्स डे सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, बल्कि हर दिन मां का सम्मान करने का संदेश देता है। कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने मां को बनाया है। मां हमेशा हमारे लिए मेहनत करती हैं, हमारी खुशी का ध्यान रखती हैं और हमें सही राह दिखाती हैं। इसलिए हमें हर दिन उनके प्रति प्यार और आदर दिखाना चाहिए।

मदर्स डे हमें यह सिखाता है कि मां हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होती हैं। उनका प्यार, त्याग और समर्पण हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी मां का सम्मान करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि वे हमारे लिए कितनी खास हैं। मां प्राण है, मां शक्ति है, मां ऊर्जा है, मां प्रेम, करुणा और ममता का पर्याय है। मां केवल जन्मदात्री ही नहीं जीवन निर्मात्री भी है।

मदर्स डे की शुरूआत की बात करें तो इसका इतिहास प्राचीन यूनानियों और रोमनों से लगाया जाता है। वह मातृ देवी रिया और साइबेले के सम्मान में इसे मनाते थे। इसे मदरिंग संडे के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल, एक समय यूनाइटेड किंगडम और यूरोप के कुछ हिस्सों में यह एक प्रमुख परंपरा थी। यह उत्सव ईसाई चर्च में लेंट, यानी ईस्टर के बाद के चौथे रविवार को मनाया जाता था।

1900 के दशक में ऐन रीव्स जार्विस की बेटी अन्ना जार्विस के प्रयासों के चलते मदर्स डे मनाया जाने लगा। अन्ना की मां ने अपना जीवन महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और गुलामी हटाने की वकालत करते हुए बिताया था। 1905 में उनकी मृत्यु के बाद, अन्ना ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का फैसला किया।

इसके बाद इसके बाद मई 1908 में उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया के ग्राफ्टन में मेथोडिस्ट चर्च में पहला आधिकारिक मदर्स डे समारोह आयोजित किया। उस दिन इस कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए। पांच साल के अंदर अमेरिका समेत कई देशों में यह सेलिब्रेट किया जाने लगा। 1914 में यूएस प्रेसिडेंट वूड्रो विल्सन ने इसे नेशनल हॉलिडे घोषित कर दिया।

भाजपा को परखने के औजार बदलने होंगे

राकेश सैन

भारतीय जनता पार्टी की बंगाल जीत ने केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषकों का भी ध्यान आकर्षित किया है। सभी अपने-अपने मापदण्डों पर इस चुनाव परिणाम को परख रहे हैं परन्तु पुराने ढर्रों पर चलते हुए फिर से गलती पर गलती दोहराते लगते हैं। यहां के विपक्ष की मानें तो यह एसआईआर के प्रयोग से निकला विजयमार्ग है तो विदेशी विश्लेषक फिर से जिंगल बैल जिंदल बैल की तरज पर साम्प्रदायिकता का गीत गाने लगे हैं। इन पांच राज्यों के चुनाव परिणाम बताते हैं कि भाजपा ने कहीं पहली बार पांव जमाए हैं, कहीं वह फिर से सत्ता में आई है तो कहीं उसने अपना जनाधार बढ़ाया है। अगर केरल जैसे राज्य में वामपंथी दलों को भाजपा के प्रभाव के डर से अयप्पा के दर्शन करने पड़ें, भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से बंजर कहे जाने वाले बंगाल में कमल की फसल लहलाने लगे, द्रविड़ राजनीति के केंद्र तमिलनाडू में उसकी आहट सुनने लगे यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि विरोधी इस दल को गलत औजारों से परख रहे हैं। विरोधी भूलते हैं कि देश का मतदाता मदिहीन नहीं है, वह सुशासन व विकास को अपनी पसंद बनाता जा रहा है। अगर कोई दल संविधान के अनुरूप काम करते हुए जनता की पसंद बन रहा है तो विरोधियों को भी अपनी सोच बदलनी होगी।

भाजपा केंद्र और बहुत से राज्यों में वर्षों से शासन में है। अंधविरोध के चरम पर जा कर भी शासन व संवैधानिक व्यवस्था के किसी मान्य मापदण्ड पर विपक्ष अभी तक ऐसा कोई मुद्दा तराश नहीं पाया है जो जनता को भी मान्य हो। यहां तक कि प्रधानमंत्री कई बार चुटकी ले चुके हैं कि सार्वजनिक जीवन में विपक्ष उनकी कोई तथ्यात्मक आलोचना करने में असफल रहा है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता तक पहुंचते ही वैश्विक वैचारिक गलियारों में भी बेचैनी पैदा हो गई है। विदेशी मीडिया के बड़े हिस्से ने भारत में

लोकतंत्र, अल्पसंख्यक अधिकार और चुनावी निष्पक्षता पर अचानक सवाल उठाने शुरू कर दिए। बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियन और अल जजीरा जैसे मंचों पर फिर से यह विमर्श तेजी से गढ़ा जाने लगा कि भारत हिन्दू राष्ट्रवाद की ऐसी दिशा में बढ़ रहा है, जहां लोकतंत्र व बहुलता खतरे में है। विदेशी मीडिया में ज्यादा चर्चा बंगाल की है। सवाल यही है कि क्या चिंता वास्तव में लोकतंत्र की है या उस सियासी बदलाव की, जिसने दशकों पुराने वामपंथ और छद्मधर्मनिरपेक्षता के वैचारिक गढ़ को ध्वस्त कर दिया? जब भाजपा हारती है, तो विदेशी मीडिया भारत की लोकतांत्रिक परिपक्वता की तारीफ करता है, पर जैसे ही वह निर्णायक जनादेश लेकर आती है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया संदेह और संस्थागत संकट की भाषा में बदल जाती है। श्रेष्ठभावना से ग्रसित पश्चिमी जगत कहीं यह तो नहीं मानता कि भारतीय मतदाताओं में राजनीतिक समझ का अभाव है ?

राष्ट्रवाद को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर अनेक विचारक स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत का राष्ट्रवाद संकीर्ण पश्चिमी राष्ट्रवाद से सर्वदा विपरीत है। पश्चिमी मीडिया भारत को अक्सर यूरोपीय राजनीतिक अनुभवों के चश्मे से देखने की कोशिश करता है। वहां राष्ट्रवाद का अर्थ सत्ता विस्तार व नस्लीय वर्चस्व रहा है। जबकि भारत में राष्ट्रवाद सांस्कृतिक, सभ्यतागत पहचान और ऐतिहासिक आत्मबोध से जुड़ा है। इसे विदेशी मीडिया समझ नहीं पाता। इसीलिए वो हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण को सीधे अल्पसंख्यक-बहुसंख्यकवाद से जोड़ देता है। यही कारण है कि बंगाल में भाजपा की जीत को पश्चिम के विश्लेषकों ने लोकतांत्रिक परिवर्तन के बजाय हिंदू राष्ट्रवादी कब्जे की तरह प्रस्तुत किया गया। एसआईआर पर अर्धसत्य दिखाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने परिणामों के बाद वोट चोरी का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को भाजपा का आयोग बताया। विदेशी मीडिया ने इन आरोपों को लगभग बिना तथ्य जांचे ही अपने विमर्श का आधार बना लिया। विशेष रूप से एसआईआर को मुस्लिम मतदाताओं को हटाने की साजिश के रूप में पेश किया गया, जबकि हटाए गए 91 लाख नामों में 63 प्रतिशत हिंदू मतदाता थे। बड़ी संख्या में नाम मृत, डुप्लिकेट, स्थायी रूप से स्थानांतरित या फर्जी पाए गए थे। इसके बावजूद विदेशी मीडिया के बड़े हिस्से ने केवल मुस्लिम वोट हटाए गए वाली जिद को प्रमुखता दी। देसी-विदेशी विश्लेषक यह भूल गए कि जिन 20 सीटों पर जाँच के बाद सबसे ज्यादा वोट काटे गए थे, उनमें से ज्यादातर पर टीएमसी ने ही कब्जा जमाया है। इन सीटों में समशेरगंज, लालगोला, भगवानगोला, रघुनाथगंज, मटियाबुर्ज, सूती, मोथाबाड़ी, गोलपोखर, मालतीपुर, चोपड़ा, सुजापुर, राजारहाट न्यू टाउन और बशीरहाट उत्तर शामिल हैं। इन सभी 13 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी को जीत मिली है। अन्य सीटों की बात करें तो फरक्का सीट पर सबसे ज्यादा 38,222 वोट काटे गए थे, लेकिन वहाँ से कॉन्ग्रेस ने जीत दर्ज की। वहीं भाजपा को जंगीपुर, रतुआ, करनदिघी, केतुग्राम, मानिकचक और मोंतेश्वर जैसी 6 सीटों पर जीत मिली। यह अकेला आँकड़ा ही उस प्रोपेगेंडा की हवा निकाल देता है जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि वोटर लिस्ट में सुधार से सिर्फ टीएमसी को नुकसान हुआ और भाजपा को फायदा पहुँचा।

अगर बड़े पैमाने पर देखें, तो जिन 187 सीटों पर 5,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए थे, वहां भाजपा ने 119 और टीएमसी ने 65 सीटों पर जीत दर्ज की। इन 187 सीटों में से 47 सीटें ऐसी थीं, जहाँ कटे हुए वोटों की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा थी। भाजपा ने जो 119 सीटें जीतीं, उनमें से 28 सीटों पर जीत का अंतर कटे हुए वोटों से कम था। इन आँकड़ों से साफ है कि कई सीटों पर कांटे की टक्कर थी और वहाँ कटे हुए वोटों की संख्या जीत के मार्जिन से ज्यादा रही। लेकिन हार का पूरा ठीकरा सिर्फ वोटर लिस्ट सुधार की प्रक्रिया पर फोड़ देना और इसे ही हार की एकमात्र वजह बताना पूरी तरह से भ्रामक और गलत है।

सच्चाई यह है कि देसी-विदेशी विश्लेषकों को नरेंद्र मोदी और भाजपा का बढ़ता राजनीतिक विस्तार विदेशी वैचारिक प्रतिष्ठानों की सबसे बड़ी बेचैनी बन चुका है। खास कर उन क्षेत्रों में यह जलन ज्यादा है जो 2024 के आम चुनावों में कांग्रेस को मिली थोड़ी राजनीतिक राहत को लेकर उत्साहित चला आरहा था। आज भाजपा अधिकांश राज्यों में प्रत्यक्ष या गठबंधन के जरिए सत्ता में है। ऐसे में भारत को हिन्दू राष्ट्रवादी लोकतंत्र और एकदलीय प्रभुत्व के खांचे में फिट करने की कोशिशें और तेज होती दिख रही हैं। परंतु बंगाल का फैसला यह भी साबित करता है कि भारत का मतदाता अपनी प्राथमिकताएं जमीन, अनुभव और आकांक्षाओं के आधार पर तय कर रहा है, न कि न्यूयॉर्क, लंदन या दोहा में बैठे नैरेटिव निर्माताओं की वैचारिक दृष्टि के अनुसार।

विदेशी विश्लेषणों में बंगाल के चुनावी परिणाम को हिन्दुत्व के उभार के रंग में रंग दिया। लेकिन वहां की जनता की नाराजगी, आर्थिक बदहाली, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीडन्, सत्ताधारियों की हिंसा, उद्योगों का पलायन जैसे कारणों की अनदेखी कर गया। आज बंगाल पर कर्ज 7.7 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच चुका है। हजारों कंपनियां राज्य छोड़ चुकी हैं। युवाओं का बड़ा वर्ग रोजगार के लिए पलायन कर रहा है। महानगरों में घरों में काम करने वाली अधिकतर महिलाएं बंगाली ही निकलती हैं। कट मनी, भर्ती घोटाले और सिंडिकेट संस्कृति जैसे मुद्दे वर्षों से जनता में असंतोष पैदा कर रहे थे।

आज का इतिहास

1810 रेव. हेनरी डंकन ने स्कॉटलैंड के रूथवेल में दुनिया का पहला वाणिज्यिक बचत बैंक खोला था।
1823 मिसिसिपी नदी को नेविगेट करने के लिए पहला स्टीमबोट फिटिंग स्नोलिंग पर आया।
1824 लंदन में नेशनल गैलरी को जनता के लिए खोला गया, कलेक्टर जॉन जूलियस एंगरस्टीन के इनफॉर्मर टाउनहाउस में।
1833 ले वैन खोई विद्रोह सम्राट मिन्ह और वियतनाम के खिलाफ शुरू हुआ।
1837 न्यूयॉर्क शहर में बैंकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में असमान-वर्ष की मंदी को ट्रिगर करते हुए, भुगतान को निलंबित कर दिया।
1837 1837 का आतंक (लड़ाई) न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ।
1857 ब्रिटिश ईस्टइंडिया कंपनी द्वारा कंपनी नियम के खिलाफ सिपाही विद्रोह शुरू हुआ।
1869 संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसौरी और सैक्रामेंटो नदियों के बीच पहला ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलमार्ग पूरा होने के उपलक्ष्य में, यूटा के प्रोमोंटरी शिखर सम्मेलन में गोल्डन स्पाइक समारोह आयोजित किया गया था।
1872 विक्टोरिया वुडहुल संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में नामित होने वाली पहली महिला बनीं।
1893 लंदन में इंपीरियल संस्थान खोला गया।
1908 वेस्ट वर्जिनिया के ग्रेफ्टन में चर्च सर्विस के दौरान पहला मदर्स डे मनाया गया।
1916 अर्नेस्ट शेकलटन और पांच साथियों ने एक लाइफहाउस में 800-नॉटिकल-मील (1,500 किमी) की यात्रा के बाद साउथगोरिया पहुंचने पर थेरस्टोन की सबसे बड़ी छोटी नाव यात्रा में से एक को पूरा किया।
1924 जे एडगर हूवर को जांच ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया गया।
1925 न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री विलियम मासी का कार्यालय में निधन हो हुआ।
1933 10 मई, 1933 को पराग्वे ने बोलीविया पर युद्ध की घोषणा की। इस संघर्ष को दोनों देशों के बीच दक्षिण अमेरिका के ग्रान चाको के उत्तरी भाग पर नियंत्रण करने के लिए चाको युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, जिसे तेल में समृद्ध माना जाता है।
1934 राजस्व अधिनियम संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी किया गया।
1936 मैनुअल अज़ाना स्पेन के नए राष्ट्रपति बने।
1937 8 वा इंपीरियल सम्मेलन लंदन में शुरू हुआ।
1940 ब्रिटिश प्रधान मंत्री नेविल चेम्बरलेन ने इस्तीफा दे दिया और अपने उत्तराधिकारी के रूप में विंस्टन चर्चिल की सिफारिश की।

भाजपा, हिंदूकृत राष्ट्रवाद, बंगाल और एक्स फैक्टर

शेखर गुप्ता

तीन गैर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों में सत्ताधारी दलों को हार का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के इन परिणामों के अलग-अलग सबक और नजरिये हैं। मैं पहले इन तीनों राज्यों के कुछ सामान्य पहलू सामने रखूंगा और फिर कुछ खास। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की।

मैं एक कहानी से शुरुआत करता हूं। श्यामल दत्ता, 1965 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे जिन्होंने 1998 से 2001 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के निदेशक के रूप में काम किया। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। बाद में 2002 से 2008 तक वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी संप्रग की सरकारों में नागालैंड के राज्यपाल रहे। वह किसी राजनीतिक दल के वफादार नहीं थे।

कोलकाता की एक उड़ान के दौरान मैंने उनसे पूछा था कि क्या भाजपा कभी पश्चिम बंगाल में जीत सकती है। उन्होंने कहा था कि बंगाल किसी भी अन्य प्रदेश की तुलना में भाजपा को अधिक खुले दिल से अपनाएगा। बस यह देखना है कि इसमें कितना वक्त लगेगा। 85 वर्षीय दत्ता सेवानिवृत्ति के बाद कोलकाता के बालीगंज में रहते हैं। मैंने उन्हें फोन करके 26 साल पहले हुई बातचीत की याद दिलाई। और पूछा कि आखिर उन्हें इतना यकीन कैसे था कि भाजपा वहां जीत जाएगी? उन्होंने कहा, 'यह बहुत पुरानी बात हो गई लेकिन शायद मैं ऐसा इसलिए कह सका क्योंकि मैं कोलकाता में वाजपेयी की रैली में उनके साथ था। वह ममता बनर्जी के घर गए थे और उन्होंने उनकी मां के पैर छुए थे।'

वहां लोगों की गर्मजोशी और भीड़ देखकर उन्हें लगा था कि बंगाल भाजपा के लिए तैयार है। उन्होंने कुछ दार्शनिक अंदाज में कहा कि उन्हें यह भी लगा था कि ममता बंगाल में भाजपा की नेता हो सकती हैं। लेकिन यह कहानी सिरे से उलट गई। ममता की तृणमूल कांग्रेस वाजपेयी के राजग की सदस्य थी और वह रेल मंत्री थीं। फरवरी 2002 के गुजरात दंगों और नरेंद्र मोदी के उभार के बीच मुस्लिम मतों की जरूरत ने ममता को राजग छोड़ने पर विवश किया। इस कहानी के कुछ सबक हैं।

1. पहला निष्कर्ष उनकी पराजय से निकलता है। अब तक कल्याणकारी योजनाओं और पहचान की राजनीति का संयोजन उनके लिए कारगर रहा। 30 फीसदी मुस्लिम वोट और महिलाओं की निष्ठा के चलते वह भाजपा की दशक भर की चुनौती के बावजूद अजेय दिखती थीं। लेकिन आखिरकार स्पष्ट नजर आने वाले विकास की कमी और वाम मोर्चा के समय की 'दादागीरी' (स्थानीय माफिया) ने उन्हें हरा दिया। निश्चित रूप से भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन सबक यह है कि केवल कल्याणकारी योजनाएं और पहचान की राजनीति बार-बार काम नहीं करतीं। चौथी बार तो बिल्कुल नहीं। विकास जरूरी है।

2. पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों क्षेत्रीय पहचान की राजनीति की सीमाओं को उजागर करते हैं। दीदी और एमके स्टालिन दोनों ने अपनी राजनीति दिल्ली, हिंदी वर्चस्व और अन्यायपूर्ण केंद्र के खिलाफ आगे बढ़ाई। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि युवा अधीर हो रहे थे। तमिलनाडु ने पश्चिम बंगाल से अधिक नौकरियां पैदा कीं, लेकिन भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश में पीछे छूटे लोग हमेशा लाभ पाने वालों से अधिक होंगे। यही असंतोष जोसेफ विजय की सफलता का कारण बना। दीदी के पास धर्मनिरपेक्षता की अपनी परिभाषा के अलावा कोई विचारधारा नहीं है और तमिल मतदाता पुरानी द्रविड़ विचारधारा से थक चुके हैं। उन्हें नयेपन की आवश्यकता थी।

3. विजय का उदय अभूतपूर्व नहीं है। हमारे पड़ोस के दो वास्तविक लोकतंत्रों यानी श्रीलंका और नेपाल में पहले ही बाहरी नेता स्थापित पार्टियों को किनारे कर चुके हैं। इससे सबक यह है कि लोग, खासकर युवा, बार-बार पुरानी राजनीति के दोहराव से ऊब सकते हैं। यदि कोई नया चेहरा नई सोच और साफ छवि के साथ सामने आता है, तो वे उसे मौका देंगे। इसका पहला संकेत हमने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के रूप में देखा, और अधिक महत्त्वपूर्ण रूप से पंजाब में, जहां अकाली दल जैसी गहरी जड़ें जमाने वाली धार्मिक क्षेत्रीय पार्टी मौजूद थी। राजनीतिक रूप से बाहरी व्यक्ति अब हमारी राजनीति का 'एक्स फैक्टर' बन गया है। याद रखिए, तमिलनाडु में श्रीलंका और नेपाल दोनों को मिलाकर भी अधिक मतदाता हैं।

4. हमने तथाकथित 'अल्पसंख्यक' वोट के हाशिए पर जाने को देखा है। विभाजन की तर्कशक्ति यही है कि मुसलमान बिखरे हुए हैं, भले ही कुछ राज्यों में उनकी संख्या उल्लेखनीय हो। उनका वोट तभी मायने रखता है जब जिन नेताओं पर वे भरोसा करते हैं, वे हिंदुओं के बड़े हिस्सों के साथ गठबंधन करें। मंडल युग में यादव नेताओं और मायावती ने जाति-आधारित समर्थन जुटाया। वे तीन-तरफा मुकाबले में लगभग 30 फीसदी वोट पाकर जीत सकते थे। लेकिन भाजपा ने हिंदू वर्चस्व का विस्तार कर कई जाति-आधारित दलों को साथ जोड़ लिया है, इसलिए 30 फीसदी वाला दौर खत्म हो गया है। यदि भाजपा को हिंदू वोट का 50 फीसदी मिल जाता है, तो उसकी जीत तय है। पश्चिम बंगाल और असम में उसे लगभग 60 फीसदी की आवश्यकता होती है। इसलिए 'धर्मनिरपेक्ष' पार्टियों को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। अन्यथा, भारत की 15 फीसदी मुस्लिम आबादी चुनावी दृष्टि से महत्त्वहीन हो जाएगी।

5. राजनीतिक वाम का अंत इतना अपरिहार्य है कि अब इस पर कोई शेखी भी नहीं बघारेगा। केरल में बड़ी हार, पश्चिम बंगाल में लगभग शून्य और तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के नेतृत्व वाले गठबंधन की पराजय ने वामपंथ को लगभग समाप्त कर दिया है। यह सशस्त्र, 'क्रांतिकारी' वामपंथ के अंत के साथ मेल खाता है।

6. क्षेत्रीय पार्टियां अब धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं। कुल मिलाकर विजय की तमिलगा वेट्री कषगम (टीवीके) का उदय संतुलन बना देता है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस को वापसी में कठिनाई होगी। असम में कभी प्रभावशाली रहा असम गण परिषद अब भाजपा की दूर की सहयोगी बन गई है। शिवसेना विभाजित है। अकाली दल अपने गौरवशाली दिनों की छाया मात्र रह गया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), द्रमुक, जनता दल (सेक्युलर) कमजोर हो चुके हैं और जनता दल (यूनाइटेड) नीतीश कुमार के साथ ढलान की ओर है। भारत राष्ट्र समिति टूट चुकी है और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) स्थायी निष्क्रियता में है। इसका अर्थ यह है कि क्षेत्रीय शक्तियां क्षीण हो रही हैं। ध्यान रहे, मैंने केवल उन्हीं पार्टियों को सूचीबद्ध किया है जिन्होंने कई बार मुख्यमंत्री पद का आनंद लिया है।

7. केरल को छोड़कर, क्षेत्रीय दलों का पतन कांग्रेस के लिए भी सकारात्मक है। इन क्षेत्रीय दलों में से कई या तो कांग्रेस से अलग होकर बने (तृणमूल, युवजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी या वाईएसआरसीपी, राकांपा), या फिर इसके वोट बैंक को खींच ले गए (समाजवादी पार्टी, बीएसपी, राष्ट्रीय जनता दल)। यदि कांग्रेस धैर्य रखकर मेहनत करने को तैयार हो। तो इन दलों का पतन कांग्रेस के लिए नए अवसर खोलता है। सवाल यह है कि क्या उसके पास कौशल, साहस और विनम्रता है? याद रखिए भाजपा ने 2016 में पश्चिम बंगाल में केवल तीन सीटों से शुरुआत की थी।

8. आखिर में, यदि आप भाजपा की सफलता का श्रेय या दोष केवल हिंदुत्व को देंगे तो यह भूल होगी। यह उससे अधिक है। यह है 'हिंदूकृत राष्ट्रवाद'। दुनिया भर के लोकतंत्रों में कठोर राष्ट्रवाद फिर लौट आया है। जब तक भाजपा के प्रतिद्वंद्वी इसे स्वीकार नहीं करते, वे और अधिक अप्रासंगिक होते जाएंगे। पश्चिम बंगाल में मतदान के अंतिम चरण की पूर्व संध्या पर निकोबार में राहुल गांधी की जो तस्वीर सामने आई है वह इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती। इसका मकसद उस परियोजना को रोकना है जिसे व्यापक जनमत भारी सामरिक महत्व का मानता है। आज के उदारवाद को सबसे पहले कठोर राष्ट्रवाद की परीक्षा में खरा उतरना होगा।

बंगाल विधानसभा में कौन होगा नेता प्रतिपक्ष!

सत्येंद्र प्रताप सिंह

ममता बनर्जी अपनी घर भवानीपुर में ही 15 हजार से अधिक मतों से चुनाव हार गई हैं। ममता बनर्जी सहित सवा एक दर्जन के करीब मंत्री और सवा एक दर्जन के करीब ही हेवीवेट नेता चुनाव हार गए हैं। नेता प्रतिपक्ष के लिए मजबूरन तीन-चार नामों में ही किसी एक को चुनना होगा।

1998 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कहा था कि भाजपा को बंगाल में लाकर ममता बनर्जी बहुत बड़ी गलती की है। करीब 28 साल बाद ममता बनर्जी को शायद यह बात ज्यादा याद आ रही होगी। ममता बनर्जी जब 2011 में सत्ता में आई थीं उस वक़्त भाजपा का खाता शून्य था। पांच साल बाद खाते में तीन और दसवें साल में 77 था। पंद्रह साल बाद भाजपा के खाते में 207 और ममता के खाते में 80 है।

कौन हो सकता है नेता प्रतिपक्ष! इससे पहले कौन कौन हार गए और कौन बच गए, इस पर एक नजर डालते हैं। ममता बनर्जी के अलावा हारने वाले मंत्रियों में अरूप बिस्वास, मलय घटक, ब्रात्य बसु, शशि पांजा, चंद्रिमा भट्टाचार्य, उदयन गुहा, सुजित बोस, रथिन घोष, ज्योतिप्रिय मल्लिक, परेशचंद्र अधिकारी, बेचाराम मन्ना, इंद्रनील सेन और मानस भुइंया शामिल हैं।

हेवीवेट और चर्चित चेहरे जो बंगाल विधानसभा में नहीं दिखेंगे, इसकी संख्या भी करीब उतनी ही है। देबाशीष कुमार, अतिन घोष, राजीव बनर्जी, गौतम देब, सब्यसाची दत्ता, अर्पिता घोष, रत्ना चट्टोपाध्याय, श्रेया पांडे, स्वप्ना बर्मन, अदिति मुंशी, शौकत मोल्ला, हुमायूं कबीर, विदेश बोस, अरुंधति मैत्रा लवली और सायन्तिका बनर्जी।

जाना पहचाना चेहरा की संख्या काफी कम है। बिमान बनर्जी, शोभनदेव चट्टोपाध्याय, फिरहाद

हकीम, जावेद खान, मदन मित्रा, नयना बंदोपाध्याय, रितोब्रत बंदोपाध्याय, कुणाल घोष और फैजुल हक़ उर्फ काजल शेख। फिरहाद हकीम और जावेद खान में से किसी एक को नेता प्रतिपक्ष बनाने से अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का मुद्दा बन सकता है।

अनुभव के आधार पर स्पीकर विमान बनर्जी और वरिष्ठ मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ही दो प्रबल दावेदार हैं। 77 वर्षीय विमान बनर्जी बारुईपुर से विधायक और मई 2011 से बंगाल विधानसभा के 10वें स्पीकर हैं। विधानसभा चलाने का 15 साल का अनुभव है। वहीं, 82 वर्षीय शोभनदेव चट्टोपाध्याय इस दफे बालीगंज से विधायक चुने गए है।

शोभनदेव चट्टोपाध्याय 1998 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित पहले विधायक हैं। तृणमूल कांग्रेस की श्रमिक शाखा, आईएनटीटीयूसी के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। 2021 में ममता बनर्जी जब नंदीग्राम में चुनाव हार गई थीं तो इन्होंने ही भवानीपुर सीट से इस्तीफा देकर ममता बनर्जी के लिए उपचुनाव का रास्ता बनाया था।

बहरहाल, ममता बनर्जी के यह दोनों ही बेहद करीबी व विश्वासपात्र हैं। ऐसे में पूरी संभावना है कि इन्हीं दोनों में से किसी एक को ममता बनर्जी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए चयन करें।

बंगाल में बीजेपी की जीत के सूत्रधार अमित शाह

विक्रम उपाध्याय

बंगाल में बीजेपी की जीत ना तो किसी जादू का परिणाम है और ना ही अप्रत्याशित ही है। इस परिणाम की अपेक्षा मीडिया, विपक्ष और यहां तक कि 15 साल शासन करने वाली टीएमसी को भी थी, क्योंकि सबको मालूम था कि बंगाल में परिवर्तन हो रहा है, और इस परिवर्तन के सूत्रधार कोई और नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बन रहे हैं। कारण साफ था कि ममता बनर्जी की सरकार से लोग ऊब चुके थे और उससे मुक्ति का विकल्प केवल उन्हें बीजेपी ही नजर आ रही थी। तृणमूल ने अपने 15 साल के शासन में बंगाल को एक अराजक राज्य में बदल दिया था। जहां कानून की रोज धज्जियां उड़ाई जा रही थी।

बलात्कार और हत्या जैसी घटनाओं पर भी शासन संवेदनशील नजर नहीं आ रहा था। पुलिस प्रशासन का पूरी तरह राजनीतिकरण हो चुका था, और अधिकारी सत्ता से जुड़े अपराधियों को बचाने में लगे थे। राज्य सरकार केंद्र से बेवजह लड़ाई ठान कर बैठी थी, और यहां तक कि लोक कल्याण से जुड़ी योजनाओं को भी जनता तक नहीं पहुंचने देती थी। भ्रष्टाचार का बोलबाला ऊपर से नीचे तक था और मंत्री एवं अधिकारी सीधे घोटाले से जुड़े हुए थे। उसके बावजूद टीएमसी हर चुनाव जीत रही थी, क्योंकि चुनाव प्रक्रियां को उसने बंधक बना लिया था।

स्थानीय प्रशासन पूरी तरह तृणमूल के साथ था। विरोध में जो भी खड़ा होता था, उसे तृणमूल के गुंडे धमकाते-मारते थे और फिर भी किसी ने खिलाफ वोट देने की हिम्मत की तो जान से मार देने में भी नहीं हिचकते थे। तृणमूल के एजेंट गांव गांव, मुहल्ले-मुहल्ले सक्रिय थे और किसी भी अन्य पार्टी को घुसने की जगह नहीं देते थे। ऐसे में बीजेपी के संगठन को तैयार करना और तृणमूल के मुकाबले खड़े करना एक असंभव सा कार्य बन गया था। लेकिन ऐसे ही असंभव कार्यों को संभव करने की महारत गृह मंत्री अमित शाह की है। अमित शाह ने पार्टी संगठन को हर स्तर पर तैयार करने और उसे अनुशासित कर चुनाव जीतने की मशीनरी में बदलने की कला गुजरात में ही विकसित कर ली थी। हर तरह के आकड़ों और तरीकों का

उपयोग कर पार्टी के विस्तार को अंतिम बूथ तक ले जाने की महारत उन्हें गुजरात में ही हासिल गया था।

अपने विश्वस्त सहयोगियों चुनाव से महीनों पहले बंगाल भेजकर बीजेपी को एक मज़बूत राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित करने का अभियान अमित शाह ने 2024 के लोक सभा चुनाव के बाद ही शुरू कर दिया था। पहले ही दिन से अमित शाह ने बंगाल में 150 से ज्यादा सीटें जितने का लक्ष्य कतीकर्ताओं के सामने रख दिया था।

2024 के लोकसभा चुनावों में केवल 12 सीटों पर मिली जीत की समीक्षा की गई और उसे आधार बनाकर पार्टी नई रणनीति में बदलाव किया ताकि 2026 में एक बड़ी वापसी सुनिश्चित की जा सके। शमिक भट्टाचार्य जैसे मुखर नेता को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लेकिन साठ ही अमित शाह ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि पुराने और अनुभवी नेताओं की उपेक्षा ना हो। संघ के साथ योजना बनाकर अमित शाह ने बंगाल के भद्रलोक यानि शहरीबुद्धिजीवीयों के बीच सघन प्रचार का काम शुरू किया। उत्तरी बंगाल के साथ तृणमूल के गढ़ वाले दक्षिण बंगाल पर भी फोकस किया गया। इससे सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को उसके घर में ही घेरने में सफलता मिली।

अमित शाह हर चुनाव में बूथ-स्तरीय प्रबंधन को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। बंगाल में भी इस पर बहुत मेहनत बीजेपी ने इस बार की। डेटा-आधारित चुनाव प्रबंधन की योजना बनाई और टीएमसी के दबदबे को खत्म कर दिया। सुवेंदु अधिकारी को पार्टी का एक प्रमुख चेहरा तो बनाया लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बंगाली भाषी नेताओं को भी बड़े पैमाने पर उतार दिया। सबके सामने लक्ष्य साफ था कि इस बार बीजेपी के वोट शेयर को 2021 के 38 I15 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 से 50 प्रतिशत तक लाना है।

बंगाल में कभी भी चुनाव शांतिपूर्ण नहीं हुआ। हर चुनाव में हिंसा का दौर देखा गया। तृणमूल ने भी पूरे राज्य में भय का माहौल कायम कर रखा था। चुनाव के बाद क्या होगा, इस चिंता में लोग अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने से हिचकते थे। लेकिन इस बार अमित शाह ने इस डर को खत्म करने की ठान ली थी। इस मुद्दे को उन्होंने सीधे तौर पर संबोधित किया। उन्होंने मतदाताओं को आश्वस्त किया कि बिना किसी डर के मतदान करें। केंद्रीय बलों की प्रत्यक्ष तैनाती तब तक रहेगी जब तक जरूरत होगी,। इससे जनता में यह विश्वास पैदा करने में मदद मिली कि वे बिना किसी संभावित खतरे के चुनाव में भागीदारी कर सकते हैं। ग्राउन्ड पर काम कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को भी बल मिला कि उनका नेतृत्व हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा है। इससे पार्टी को जमीनी स्तर पर काम करना औरआसान हो गया।

बीजेपी के सामने सत्ता-विरोधी मुद्दों की कमी नहीं थी। तृणमूल भ्रष्टाचार, घुसपैठ, महिला सुरक्षा और रोजगार के मुद्दे पर बैक फुट पर थी। बीजेपी ने अपने प्रचार का फोकस भी इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित रखा और टीएमसी को भी इन्हीं मुद्दे पर घेरे रखने में सफलता भी पाई। सत्ताधारी पार्टी इससे बौखलाहट की शिकार हो गई। अंत में सांस्कृतिक प्रतीकवाद का मुद्दा उछालना शुरू किया, पर यहाँ भी अमित शाह ने अपने राष्ट्रवादी एजेंडे को स्थानीय बंगाली भावनाओं के साथ जोड़ दिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को असली बंगाली अस्मिता की पहचान के रूप में प्रस्तुत किया। चुनाव परिणाम बताते हैं कि अमित शाह ने बीजेपी के जनाधार को उत्तरी बंगाल के जलपाईगुड़ी और कूच बिहार से लेकर दक्षिण बंगाल तक फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई। दोनों चरणों के मतदान में 91 प्रतिशत से अधिक भागीदारी के साथ, यह स्पष्ट था कि अधिक लोग मतदान करने के लिए आगे आ रहे थे, और बीजेपी के पक्ष में वोट डाल रहे थे। 4 मई 2026 को बीजेपी के पक्ष में जो राजनीतिक लहर देखने को मिली, उसके बड़े सूत्रधार अमित शाह रहे।

स्पष्ट जनादेश, नई सरकारों की होगी अग्निपरीक्षा

मृत्युंजय दीक्षित

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आ चुके हैं। नई सरकारों के गठन की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के ये विधानसभा चुनाव परिणाम कई स्पष्ट संकेत देने वाले हैं। बंगाल, असम, और पुदुचेरी ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भाजपा व राजग गठबंध को दो तिहाई बहुमत के साथ चुना वहीं तमिलनाडु और केरल में भी सत्ता बदल गई। बंगाल, असम और पुदुचेरी में विकास, कल्याणकारी योजनाओं व हिंदुत्व का कमाल रहा। असम में कल्याणकारी योजनाओं के सहारे भाजपा जहां महिलाओं और युवाओं को साधने में सफल रही वहीं मुख्यंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ मुहिम छेड़कर नस्ल, क्षेत्र और भाषा में बनते हिंदुओं को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। असम और बंगाल की जनता को भाजपा यह भरोसा दिलाने में सफल रही कि केवल भाजपा ही बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या से मुक्ति दिला सकती है।

बंगाल और असम के बाद सबसे अधिक चर्चा तमिलनाडु को लेकर हो रही है। तमिलनाडु के चुनाव परिणामों ने सभी को हैरान कर दिया है। एक बार द्रमुक और एक बार अन्नाद्रमुक का मिथक टूट गया है। फिल्म स्टार विजय की झोली वोटों से भरी है। केरलम में पराजय के बाद देश भर से वामपंथी सरकारों का अंत हो चुका है तथापि वह अपना राजनैतिक और वैचारिक अस्तित्व बचाए रखने के लिए दो विधायकों के बल पर तमिलनाडु में एक्टर थलपति विजय की नई सरकार मे घुस रही है। सभी राज्य विधानसभाओं में भाजपा का खाता खुल चुका है। पहली बार केरलम में भाजपा के तीन व

तमिलनाडु में एक विधायक जीतने में सफल रहे हैं।

तमिलनाडु में थलपति विजय की सरकार- तमिलनाडु की जनता द्रविड़ राजनीति से हताश और निराश हो चुकी थी। कभी द्रमुक और कभी अन्ना द्रमुक राज्य इनके बीच में झूलता रहता था। तमिल राजनीति में फिल्मी कलाकारों की अहम भूमिका रही है एम. जी. रामचंद्रन से लेकर करुणानिधि और जयललिता जैसे सितारों ने वहां की राजनीति में अहम भूमिका निभाई और लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे।

तमिलनाडु में एक्टर थलपति विजय की इतनी प्रचंड लहर चली कि मुख्यमंत्री स्टालिन अपनी सीट तक हार गए। इस लहर का आभास किसी भी राजनैतिक विश्लेषक को नही था। एक्टर थलपति विजय की विजय में मुख्य भूमिका उनके चुनावी वायदों ने की है जो अधिकांशत: मुफ्त की रेवड़ी वाले हैं। विवाह के लिए महिलाओं को 22 कैरेट का आठ ग्राम सोना देने से लेकर 60 सल से कम आयु की महिलाओं को 2500 रुपए मासिक सहायता प्रति परिवार छह फ्री सिलेंडर देने का वादा काम कर गया। गरीब दुल्हनों के लिए रेशमी साड़ी और महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों के लिए पांच लाख रुपए तक के बयाज मुक्त ऋ्षा का आश्वासन भी विजय ने दिया है। थलपति विजय ने वैसे ही कई लोक लुभावन वायदे किये है जैसे कभी आप नेता अरविंद केजरीवाल किया करते थे। यह थलपति विजय तमिलनाडु के केजरीवाल सिद्ध हो सकते हैं।

ईसाई पिता ओर हिंदू मां की संतान विजय ने अपनी पार्टी की विचारधारा तैयार करने में द्रविड़ विचारधारा और तमिल राष्ट्रवाद के तत्वों को जोड़ा है। इनकी पार्टी तमिलगा वेटी कझागम की स्थापना फरवरी 2024 में हुई, जो तमिलनाडु और पुदुचेरी तक फैली हुई है। लोग सेाच रहे हैं कि विजय की आखिर इतनी बड़ी विजय कैसे हो गईङ्क विजय लम्बे समय से कई घरों के चूल्हों के ईंधन, बेटियों की पढ़ाई ओर बहनों की शादी का खर्च लगातार उठा रहे थे। उनके वोटबैक में सबसे बड़ी हिस्सेदारी महिलाओं और युवाओं की रही है। वह अपनी फिल्मों में गरीबों के मसीहा के तौर पर पेश किए जाते थे जिसका परिणाम अब सबके सामने है। विजय की चुनावी जनसभाओं में अभूवपूर्व भीड़ उमड़ रही थी किंतु कोई राजनैतिक विश्लेषक यह मानकर नहीं चल रहा था कि वह सरकार बनाने तक पहुंच जाएंगे।

तमिलनाडु में यदि कोई सबसे बड़ा परजीवी दल साबित हुआ है तो वह कांग्रेस है, क्या उसने हर बार की तरह अपना अस्तित्व बचाये रखने के लिए एक और क्षेत्रीय दल की सरकार में गठबंधन के बहाने सेंधमारी कर ली है। जो दल कांग्रेस के साथ गए व कांग्रेस जिन दलों के साथ गई उन दलों का क्या हाल हो रहा है सभी को पता है। वैसे अभी थलपति विजय का शपथ ग्रहण समारोह भी ग्रहण ग्रस्त लग रहा है।

राउत का ट्रंप को पत्र: विपक्षी नेताओं की देशभक्ति पर सवाल

नीरज कुमार दुबे

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन के कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं अब केवल राजनीतिक असहमति तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि वह भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े करती दिखाई दे रही हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखना और ममता बनर्जी द्वारा अंतरराष्ट्रीय अदालत जाने की चेतावनी देना इसी प्रवृत्ति का ताजा उदाहरण है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देश के आंतरिक मामलों को विदेशी शक्तियों और वैश्विक मंचों तक ले जाना लोकतंत्र की रक्षा है या फिर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास? हम आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लिखे अपने पत्र में पश्चिम बंगाल चुनावों को भय, दबाव और कथित धांधली से प्रभावित बताया। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर भी आरोप लगाए। हैरानी की बात यह है कि यह सब उस समय कहा जा रहा है जब भारत का चुनाव आयोग विश्व की सबसे विश्वसनीय और विशाल चुनावी संस्थाओं में गिना जाता है। यदि किसी दल को चुनाव परिणाम स्वीकार नहीं हैं, तो उसके लिए न्यायपालिका, जन आंदोलन और संवैधानिक प्रक्रियाएं मौजूद हैं। फिर विदेशी राष्ट्रपति को पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या भारत इतना कमजोर लोकतंत्र है कि यहां के चुनावों का फैसला विदेशी नेताओं की राय से तय होगा? क्या विपक्ष यह संदेश देना चाहता है कि भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर उसे भरोसा नहीं है? यदि हर हार के बाद अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाकर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कठघरे में खड़ा किया जाएगा, तो इससे दुनिया में भारत की छवि पर क्या असर पड़ेगा? इस पूरे विवाद में ममता बनर्जी का बयान भी कम गंभीर नहीं है। चुनाव हारने के बाद उनका यह कहना कि वह अंतरराष्ट्रीय अदालत तक जाएंगी, कई सवाल खड़े करता है। क्या किसी राज्य के चुनावी परिणाम को लेकर संयुक्त राष्ट्र की न्यायिक संस्था में जाने की बात करना भारत की संप्रभुता पर प्रश्नचिह्न लगाने जैसा नहीं है? जब देश का संविधान, सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग मौजूद हैं, तब विदेशी अदालतों की चर्चा क्यों? दरअसल यह वही राजनीति है जिसमें जब तक सत्ता हाथ में रहे तब तक संस्थाएं निष्पक्ष लगती हैं, लेकिन हार मिलते ही चुनाव आयोग, सुरक्षा बल, न्यायपालिका और लोकतंत्र सब कटघरे में खड़े कर दिए जाते हैं। यह प्रवृत्ति केवल राजनीतिक असंतोष नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के विश्वास को कमजोर करने का प्रयास भी मानी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या विपक्षी दल अपनी राजनीतिक हार को स्वीकार करने का साहस खो चुके हैं? क्या लोकतंत्र केवल तब तक सही है जब तक परिणाम उनके पक्ष में आएं? यदि हर चुनाव के बाद विदेशी शक्तियों से हस्तक्षेप की मांग की जाएगी, तो क्या यह देश की आंतरिक संप्रभुता के खिलाफ कदम नहीं माना जाएगा? भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां सत्ता परिवर्तन चुनावों के माध्यम से होता है, अदालतें स्वतंत्र हैं और मीडिया पूरी तरह सक्रिय है। ऐसे में विदेशी नेताओं और अंतरराष्ट्रीय मंचों को भारत के घरेलू राजनीतिक विवादों में घसीटना न केवल राजनीतिक अपरिपक्वता दर्शाता है, बल्कि यह देश की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन देश की छवि और संस्थाओं की विश्वसनीयता से खिलवाड़ किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। देखा जाये तो लोकतंत्र में हार और जीत दोनों को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी लोकतांत्रिक मर्यादा होती है। लेकिन संजय राउत जैसे लोग जोकि खुद करोड़ों के घोटाले के आरोप से जुड़े हैं और जेल काट चुके हैं, वह भारत के लोकतंत्र की शुचिता और जनमत की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं। यहां एक सवाल यह भी उठता है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गयी बधाई विपक्ष को इतनी चुभ क्यों रही है? साथ ही संजय राउत भारतीय लोकतंत्र को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी देखना चाहिए कि स्वयं अमेरिका में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर कितने गंभीर सवाल उठ चुके हैं। दुनिया ने देखा कि वर्ष 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव परिणाम स्वीकार करने से इंकार कर दिया था। चुनावी धांधली के आरोपों को लेकर उनके समर्थकों ने अमेरिकी संसद भवन कैपिटल हिल पर हमला तक कर दिया था, जिसे अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना गया।

नोरा फतेही ने महिला आयोग के सामने मांगी माफी
अनाथ बच्चियों की शिक्षा का उठाया जिम्मा

कन्नड़ फिल्म 'केडी द डेविल' के गाने 'सरके चुनर' में अपनी परफॉर्मेंस को लेकर विवादों में घिरीं अभिनेत्री नोरा फतेही गुरुवार को राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश हुईं। आयोग के समक्ष अभिनेत्री ने अपनी बात रखते हुए न केवल गलती स्वीकार की बल्कि भविष्य के लिए एक बड़ा फैसला भी लिया। नोरा ने राष्ट्रीय महिला आयोग के बाहर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या महिलाओं की छवि को गलत तरीके से पेश करना नहीं था। नोरा ने कहा, मैं अपने किए पर माफी मांगती हूं, मेरा उद्देश्य किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं बस एक ऐसी स्थिति में फंस गई थी, जहां चीजें विवादित हो गईं। एक कलाकार होने के नाते मुझे जिम्मेदार होना चाहिए, इसलिए मैं तहे दिल से माफी मांगती हूं।

उन्होंने महिला आयोग के सदस्यों का आभार जताते हुए कहा कि आयोग ने उनकी बात को बहुत ही दयालुता और संवेदनशीलता के साथ सुना। नोरा ने कहा, ₹हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई है, सारी बातें लिखित में पूरी कर ली है। अब हमने फैसला किया है कि हमें समाज के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहिए। इसी सोच के साथ हमने कुछ अनाथ लड़कियों की पढ़ाई का खर्च उठाने का निर्णय लिया है। धन्यवाद।

इससे पहले इसी मामले में संजय दत्त भी 27 अप्रैल को महिला आयोग के सामने पेश हुए थे। सुनवाई के दौरान संजय दत्त ने भी आयोग से माफी मांगी थी और सामाजिक कल्याण तथा महिला सशक्तीकरण की दिशा में कदम उठाते हुए 50 आदिवासी बच्चियों की पढ़ाई का खर्च उठाने का ऐलान किया था।

बता दें कि फिल्म के गाने 'सरके चुनर' के रिलीज होने के बाद से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों की भारी नाराजगी देखने को मिली थी। कई लोगों ने आरोप लगाया था कि इस तरह के गाने अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं, जबकि कुछ लोगों ने कलाकारों की सामाजिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़े किए थे। बढ़ते विवाद को देखते हुए आयोग ने नोरा फतेही को नोटिस भेजा और व्यक्तिगत रूप से मौजूद होकर सफाई देने के लिए कहा था।

प्रियंका चोपड़ा ने खोए लाखों फॉलोअर्स, एक रात में कैसे गिरी पॉपुलैरिटी; जानिए असल वजह

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने हाल ही में कई फेक अकाउंट्स पर शिकंजा कसा है। इस प्रक्रिया में कई फेक अकाउंट और बॉट हटाने की कार्यवाही की गई है। इसके चलते हाल ही में प्रियंका चोपड़ा और काइली जेनर जैसे ग्लोबल स्टार्स के भी फॉलोवर्स कम हो गए। जानें किसे कितना पड़ा फर्क?

प्रियंका चोपड़ा

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के कुछ दिनों पहले तक इंस्टाग्राम पर 94.5 मिलियन फॉलोअर्स थे। अब इंस्टाग्राम के फेक अकाउंट्स पर की गई कार्यवाही के बाद बीते दो दिनों में उनके करीब 1.1 मिलियन फॉलोअर्स घट गए।

सबरीना कारपेंटर और काइली जेनर को भी बड़ा झटका

इंस्टाग्राम द्वारा किए गए इस पर्ज के चलते सबरीना कारपेंटर ने और काइली जेनर जैसे बड़े सेलेब्स ने भी कई मिलियन फॉलोअर्स खो दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबरीना ने करीबन 429 हजार और काइली को लगभग 14 मिलियन फॉलोअर्स का नुकसान उठाना पड़ा। इसके साथ ही टेलर स्विफ्ट के भी 4 मिलियन फॉलोअर्स कम हुए।

कई एक्ट्रेस के हुए फॉलोवर्स कम

सिर्फ प्रियंका और सबरीना ही नहीं कई स्टार्स के फॉलोवर्स कम हो गए। इस लिस्ट में सेलिना गोमेज, शकीरा, माइली सायरस और लेडी गागा जैसी कई फेमस हस्तियों के नाम शामिल हैं। बताते चलें कि इंस्टाग्राम के ऐसा करने से हर साल कई सेलेब्स के अकाउंट्स के वास्तविकता का भी पता चलता है।

रश्मिका मंदाना से क्यों आकर्षित होती हैं कृति सेनन?
साझा किया 'कॉकटेल 2' में काम करने का अनुभव

अभिनेत्री कृति सेनन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर चर्चाओं में हैं। फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। पहली बार कृति सेनन और रश्मिका मंदाना साथ में नजर आएंगी। अक्सर जब दो ए लिस्ट एक्ट्रेस एक ही फिल्म में आती हैं, तो चर्चाएं बटोरती हैं। अब हाल ही में कृति ने रश्मिका के साथ काम करने के अनुभव को साझा किया है।

रश्मिका बहुत अच्छी हैं

हाल ही में एक अवॉर्ड इवेंट में कृति सेनन ने रश्मिका मंदाना के साथ 'कॉकटेल 2' में काम करने के अनुभव के बारे में बताया। एक्ट्रेस ने कहा कि रश्मिका बहुत ही सच्ची, दयालु, प्यारी और मिलनसार हैं। उनमें जरा भी इनसिक्योरिटी नहीं है। बस अच्छाई ही अच्छाई है और मुझे लगता है कि मैं पॉजिटिव एनर्जी से अट्रैक्ट होती हूं। अगर मुझे किसी की ऊर्जा और पॉजिटिविटी महसूस होती है, तो मैं उसकी ओर आकर्षित हो जाती हूं। मुझे उनके साथ काम करके बहुत मजा आया, और वह कमाल की हैं। मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूं।

यह सीक्वल नहीं है

कृति ने 'कॉकटेल 2' और 2012 में आई 'कॉकटेल' के बीच होने वाली तुलना पर भी बात की। एक्ट्रेस ने स्पष्ट किया कि यह 'कॉकटेल' का सीधा सीक्वल नहीं है। यह एक अलग कहानी और किरदारों वाली फ्रेंचाइज फिल्म है। तुलनाओं के बारे में बात करते हुए कृति ने कहा कि मुझे यकीन है कि तुलना तो होगी ही, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह कोई सीक्वल नहीं है। यह एक फ्रेंचाइज है। इसलिए यह एक अलग ही माहौल वाली फ्रेंचाइज है और इसके किरदार अलग-अलग हैं।

साल 2012 में आई 'कॉकटेल' में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी प्रमुख भूमिका में नजर आए हैं। 'कॉकटेल' अपने संगीत, किरदारों और आधुनिक रिश्तों के ड्रामे के लिए कई साल से एक कल्ट फिल्म बन गई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही थी और इसे पसंद किया गया था।

19 जून को रिलीज होगी 'कॉकटेल 2'

होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित 'कॉकटेल 2' 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म की शूटिंग से जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन सामने आने के बाद से ही दर्शकों में उत्सुकता बढ़ गई है। कई लोगों का मानना है कि फिल्म शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना के बीच लव ट्रायंगल पर आधारित होगी। निर्देशक होमी अदजानिया ने भी इन अफवाहों पर मजाकिया प्रतिक्रिया दी थी। फिल्म का गाना 'जब तलक' भी काफी पॉपुलर हो रहा है।

'उतरन' से लोगों के दिल में उतर गई थीं टीना दत्ता

टीना ने बाल कलाकार के तौर पर अपने कॅरियर की शुरुआत की थी. उन्होंने 1997 में आई बंगाली फिल्म 'माता पिता संतान' में काम किया था. इसके बाद उन्होंने 'चोखेर बाली' और 'परिणीता' में भी किरदार निभाया था. एक्ट्रेस के तौर पर छोटे पर्दे पर उन्होंने बांग्ला टीवी से की. उन्होंने 2007 में टीवी शो 'खेला' किया. इसमें उनके काम को काफी पसंद किया गया. टीना की खूबसूरती और एक्टिंग के कारण उन्हें पहचान मिलने लगी और 2009 में उन्होंने हिंदी टीवी शो 'उतरन' में काम करना शुरू किया. इस शो ने टीना को काफी फेम दिलाई और इसके जरिए वे हर दर्शक के दिल में जगह बनाने में कामयाब हुईं.

2015 तक वे इस शो से जुड़ी रहीं और अपनी प्रतिभा से अलग पहचान बनाई. 2010 में ड्राम सीरीज के लिए उन्हें गिल्ड बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड भी मिला. टीवी की दुनिया में काम करके टीना ने कई अवॉर्ड अपने नाम किए. इसके बाद वे रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' में भी नजर आईं.

टीना बीते दिनों टीना वेब सीरीज 'नक्सलबारी' में राजीव खंडलेवाल के साथ नजर आई थीं. इसके लिए उन्हें ओटीटी डेब्यू अवॉर्ड मिला था.

इन दिनों टीना 'बिग बॉस 16' में नजर आ रही हैं. शो में उनकी सुंबुल के साथ तकरार चर्चा का विषय बनी हुई है.

बहरूपिया बने रणदीप हुड्डा को देख चौंके फैंस
'इंस्पेक्टर अविनाश' के हालिया रिलीज ट्रेलर पर जमकर मिले व्यूज

साल 2023 में रणदीप हुड्डा एक सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश' में नजर आए थे। इस सीरीज का अगला पार्ट 15 मई से जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगा। हालिया रिलीज इसके ट्रेलर में कहानी की झलक मिली। इस बार भी सीरीज में अपराध और राजनीति का जबरदस्त खेल देखने को मिलेगा। इंस्पेक्टर अविनाश अपराधियों को पकड़ने के लिए बहरूपिए के तौर पर इस बार सीरीज में नजर आएगा। इस सीरीज के ट्रेलर और रणदीप हुड्डा के लुक को देखकर फैंस चौंक गए हैं। ट्रेलर को जमकर व्यूज मिल रहे हैं।

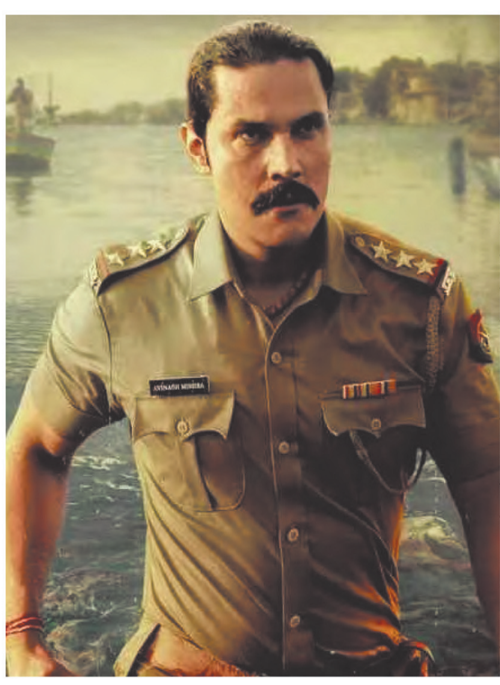

दो दिन में ट्रेलर को मिले 56 लाख व्यूज

रणदीप हुड्डा की इस सीरीज के ट्रेलर को रिलीज हुए दो दिन हुए हैं। इंस्टाग्राम पर इस ट्रेलर को 50 लाख व्यूज मिल चुके हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर इसे 6 लाख व्यूज मिले हैं। फैंस को इस सीरीज का काफी वक्त से इंतजार था। यह सीरीज लगभग तीन साल बाद वापसी कर रही है।

फैंस ने रणदीप हुड्डा के लुक और अंदाज पर दिए रिएक्शन

फैंस को रणदीप हुड्डा का सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश' में अंदाज और अभिनय पसंद आया है। कई यूजर्स सीरीज देखने के लिए एक्साइटेड है। एक यूजर ने लिखा, 'तीन साल का इंतजार।' इसी तरह के कई कमेंट्स फैंस ने किए हैं। किसी फैन ने इसे रणदीप हुड्डा की बेस्ट परफॉर्मेंस बताया है। कई फैंस ने सिर्फ हार्ट, फायर इमोजी रणदीप के लिए शेयर किए हैं।

असल कहानी पर आधारित है सीरीज

'इंस्पेक्टर अविनाश' उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी अविनाश मिश्रा पर आधारित है। राज्य में होने वाले अपराधों से वह और उनकी टीम कैसे निपटे थे, यही सीरीज की भी कहानी है। इस सीरीज में अमित सियाल, अभिमन्यु सिंह, शलीन भनोट और उर्वशी रौतेला जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। यह सभी पहले सीजन का भी हिस्सा था।

मैं हमेशा अपने लिए तैयार होती हूं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं : कृतिका कामरा

फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में फैशन सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि यह कलाकारों की पहचान का अहम हिस्सा बन चुका है। हर इवेंट और फोटोशूट में सितारों का लुक चर्चा का विषय बन जाता है। ऐसे में कई बार यह सवाल भी उठता है कि कलाकार खुद के लिए तैयार होते हैं या फिर पब्लिक इमेज को ध्यान में रखकर। इसी मुद्दे पर अभिनेत्री कृतिका कामरा ने खुलकर अपनी राय रखी। कृतिका ने कहा कि उन्होंने हमेशा अपने लिए कपड़े पहने हैं और फैशन उनके लिए आत्मविश्वास और खुशी से जुड़ा हुआ है। कृतिका कामरा ने कहा, मुझे बहुत जल्द ही यह समझ आ गई थी कि मुझे सजना-संवरना और फैशन काफी पसंद है। मैं खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए तैयार होती हूं। अच्छे कपड़े पहनने और खुद को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का असर मेरे पूरे दिन पर पड़ता है। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है और मैं अपने काम में ज्यादा सकारात्मक महसूस करती हूं।

कृतिका कामरा ने आगे बताया, "मैंने नई दिल्ली के एक डिजाइन स्कूल में फैशन कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है। इसी वजह से मैं फैशन की दुनिया को एक अलग नजरिए से देखती हूं। मुझे यह जानने में दिलचस्पी रहती है कि किसी कपड़े को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, किसी खास टेक्सटाइल को तैयार करने की प्रक्रिया क्या होती है और डिजाइनिंग के पीछे कितना काम छिपा होता है। जब इंसान किसी चीज की मेहनत को समझता है, तो उसके प्रति सम्मान भी बढ़ जाता है।"

अभिनेत्री ने कहा, "मैं फैशन इंडस्ट्री में चल रहे नए ट्रेंड्स से भी खुद को अपडेट रखती हूं, लेकिन हमेशा से वही पहनती हूं, जिसमें मैं खुद को सहज और आत्मविश्वासी महसूस करती हूं। मैंने कभी किसी को खुश करने या इम्प्रेस करने के लिए कपड़े नहीं पहने। फैशन का असली मतलब वही है, जब इंसान अपने लिए तैयार हो और अपने व्यक्तित्व को खुलकर जी सके।" कृतिका कामरा ने महिलाओं के नजरिए से फैशन को लेकर भी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा, "अगर मुझे किसी की तारीफ सबसे ज्यादा खुशी देती है, तो वह मेरी महिला दोस्तों या दूसरी महिलाओं की होती है। महिलाएं फैशन को बहुत अलग और बारीकी से देखती हैं। वे छोटे-छोटे डिटेल्स पर ध्यान देती हैं, इसलिए उनकी राय ज्यादा खास लगती है। मुझे महिलाओं से मिलने वाला फीडबैक सबसे ज्यादा पसंद आता है।" उन्होंने कहा, "काम की वजह से मुझे कई बेहतरीन डिजाइनर्स और स्टाइलिस्ट्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूं कि मुझे इतने प्रतिभाशाली लोगों के साथ काम करने का अनुभव मिला। मैं अक्सर डिजाइनर्स और स्टाइलिस्ट्स के काम से प्रेरित होती हूं लेकिन जब मैं अपना लुक तैयार करती हूं, तो उसमें मेरी अपनी पसंद भी शामिल होती है।"

अभिनेत्री ने कहा, "मैं अपनी टीम के साथ मिलकर तय करती हूं कि कौन-सा लुक मुझ पर अच्छा लगेगा और किस तरह मैं खुद को सबसे बेहतर तरीके से पेश कर सकती हूं। मैं फैशन को दिल से एंजॉय करती हूं और शायद यही वजह है कि मेरे फैसले काफी स्वाभाविक होते हैं।"

निया और अंकिता ने बताया कैसे उनकी मां ने संवारा करियर

'मदर्स डे' आने से पहले टेलीविजन इंडस्ट्री की दो मशहूर अभिनेत्रियों, निया शर्मा और अंकिता लोखंडे, ने अपनी माताओं के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया है। कलर्स टीवी के लोकप्रिय शो 'लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' का हिस्सा बनीं इन अभिनेत्रियों ने बताया कि कैसे उनकी माताओं ने उनके करियर और व्यक्तित्व को गढ़ा है। अभिनेत्री निया शर्मा अपने बोल्ड लुक्स और बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। निया ने बताया कि उनका निडर स्वभाव मां की विरासत है। अभिनेत्री कहती हैं, ₹मैंने अपनी मां को जीवन की कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करते देखा है। उनकी वही हिम्मत आज मेरे आत्मविश्वास की नींव है। निया ने अपनी मां के साथ जुड़ा एक बेहद मजेदार किस्सा भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि एक ट्रिप के दौरान वे एक 'हॉप-ऑन हॉप-ऑफ' बस में अपनी मां को खो बैठी थीं। निया और उनका परिवार परेशान होकर सबको अलर्ट कर रहा था, लेकिन घंटों बाद उनकी मां बस की छत पर आराम से बैठी शहर के वीडियो बनाती हुई मिलीं। निया कहती हैं, वह अफरा-तफरी को भी यादगार पल में बदल देती हैं।

दूसरी ओर अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने जीवन में 'दो माताओं' के होने को अपनी सबसे बड़ी खुशकिस्मती बताया। अंकिता ने कहा, एक मां ने मुझे जन्म दिया, तो दूसरी मेरी सास ने मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाकर एक नया घर और बिना शर्त प्यार दिया।

अभिनेत्री ने आगे कहा, मेरी दोनों मां मेरे दो स्तंभ हैं। हर दिन, मैं उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार महसूस करती हूं। उनकी दुआएं ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं और उनकी खुशी ही मेरे लिए मायने रखती है। यह कितना शानदार है कि मुझे अपनी दोनों मां का आशीर्वाद मिला है। 'लाफ्टर शेफ्स' शो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी ताकत के इन दो स्तंभों को और उन सभी मां को जो अपने बच्चों की परवरिश का शानदार काम कर रही हैं। 'मदर्स डे' की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

ममता ने बदला एक्स प्रोफाइल क्या यह हार की स्वीकृति है?

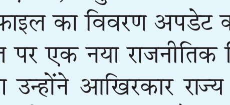

कोलकाता। सुवेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ घंटों बाद ही तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी ने एक्स पर अपनी प्रोफाइल का विवरण अपडेट कर दिया, जिससे इस बात पर एक नया राजनीतिक विवाद छिड़ गया कि क्या उन्होंने आखिरकार राज्य में भाजपा की जीत को स्वीकार कर लिया है। बनर्जी की प्रोफाइल में अब उन्हें अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री (15वीं, 16वीं और 17वीं विधानसभा) के रूप में वर्णित किया गया है। इससे पहले, उनकी प्रोफाइल में उन्हें माननीय मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के रूप में संबोधित किया गया था। यह बदलाव कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद हुआ, जहां भाजपा ने राज्य में अपनी पहली सरकार का गठन किया। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा ने भारी बहुमत हासिल करते हुए 207 सीटें जीतीं।

हम भाजपा को ईवीएम से ही हराएंगे : अखिलेश यादव

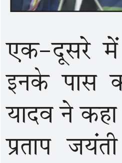

लखनऊ। अखिलेश यादव ने लखनऊ के सपा कार्यालय में शनिवार को प्रेसवार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई काम नहीं है, ये लोग नकारात्मकता फैलाते हैं, एक-दूसरे में झगड़ा लड़वाते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई काम हो तो बताएं। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर महाराणा प्रताप जयंती पर दो दिन का अवकाश दिया जाएगा। गोमती रिवर फ्रंट पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने की घोषणा की। प्रतिमा में चेतक और भाला सोने का होगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, उन्होंने ही लॉ एंड ऑर्डर को जीरो कर दिया है। ईवीएम के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यूके में हाल ही में बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं। सवाल उठाया कि क्या भारत इंग्लैंड से आगे है। समाजवादी पार्टी ईवीएम से ही भाजपा को हराएगी।

पंजाब में ईडी रेड पर भड़के सीएम भगवंत मान

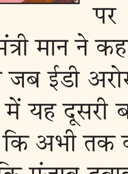

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को भाजपा पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दुरुपयोग का आरोप लगाया। ईडी ने पंजाब के मंत्री और विधायक संजीव अरोरा के घर पर फिर से तलाशी ली। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि एक साल में यह तीसरी बार है जब ईडी अरोरा के घर आई है और पिछले महीने में यह दूसरी बार है। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि पंजाब दबाव या राजनीतिक हथकंडों के आगे नहीं झुकेगा। एक पोस्ट में पंजाब के मुख्यमंत्री ने लिखा कि आज एक बार फिर भाजपा की ईडी संजीव अरोरा के घर आई है। एक साल में यह तीसरी बार है जब भाजपा की ईडी उनके घर आई है। और पिछले एक महीने में यह दूसरी बार है। फिर भी, उन्हें कुछ नहीं मिला है। मैं मोदी जी को बताना चाहता हूं कि पंजाब गुरुओं की भूमि है, जिसे औरंगजेब भी अपने अधीन नहीं कर सका।

दिनाकरन ने विजय की टीवीके के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

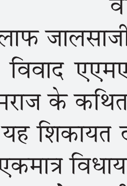

चेन्नई। तमिलनाडु में सरकार बनाने की रस्साकशी अब पुलिस स्टेशन तक जा पहुँची है। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कज़गम (एएमएमके) के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) के खिलाफ जालसाजी की शिकायत दर्ज कराई है। यह पूरा विवाद एएमएमके के इकलौते विधायक एस. कामराज के कथित समर्थन पत्र को लेकर शुरू हुआ है। यह शिकायत दोनों पार्टियों के बीच एएमएमके के एकमात्र विधायक, एस. कामराज के समर्थन को लेकर बढ़ते राजनीतिक टकराव के बीच आई है। यह ताज़ा घटनाक्रम तब सामने आया जब टीटीवी दिनाकरन ने आरोप लगाया कि टीवीके ने गवर्नर के साथ विधायक कामराज के पत्र की एक फर्जी कॉपी साझा की थी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी थी। इन आरोपों के बाद, टीवीके ने कामराज का एक वीडियो जारी किया जिसमें वह विजय के नेतृत्व वाली पार्टी के समर्थन में एक पत्र लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं।

भाजपा के लिए पार्टियां तोड़ रहीं एजेंसियां : केजरीवाल

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने और उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि शनिवार सुबह से पंजाब के मंत्री संजीव अरोरा के आवास पर ईडी की छापेमारी जारी है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से हमने देखा है कि सीबीआई और ईडी भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के बजाय अन्य पार्टियों को तोड़ने और अन्य राजनीतिक नेताओं को धमकाकर उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर करने का काम कर रही हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि ईडी की छापेमारी इसी दिशा में उठाया गया कदम है।

बंगाल में भाजपा सरकार, शुभेंदु के सामने 5 बड़ी चुनौतियां

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में शनिवार को एक नया अध्याय जुड़ गया। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। वह राज्य में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में यह भव्य समारोह हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। भाजपा ने इस चुनाव में 207 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है। इसके साथ ही राज्य में तृणमूल कांग्रेस का 15 साल पुराना शासन खत्म हो गया है। भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान पोरिबर्तन का नारा दिया था। अब शुभेंदु अधिकारी के कंधों पर इस वादे को सच करने की बड़ी जिम्मेदारी है। आइए हम आपको शुभेंदु सरकार के सामने की पांच प्रमुख चुनौतियों के बारे में बताते हैं।

1- बंगाल में अवैध घुसपैठ को रोकना

बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सामने सबसे पहली और बड़ी चुनौती अवैध घुसपैठ को रोकना है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं बांग्लादेश से सटी हुई हैं। इस कारण राज्य में घुसपैठ एक गंभीर समस्या बनी हुई है। घुसपैठ पर लगाम लगाना राज्य और देश की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था। घुसपैठ की वजह से राज्य की सुरक्षा और संसाधनों पर हमेशा दबाव बना रहता है। शुभेंदु अधिकारी के लिए इस समस्या का समाधान करना एक बड़ी परीक्षा होगी। अब यह देखना होगा कि नई सरकार इस समस्या से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है।

2- गौ-तस्करी पर पूरी तरह रोक लगाना

पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के साथ ही गौ-तस्करी का मुद्दा चर्चा में है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सामने इस अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करना एक बड़ी चुनौती है। राज्य के सीमावर्ती जिलों में गौ-तस्करी की समस्या वर्षों से बनी हुई है। तस्करों का जाल इतना गहरा है कि यह राज्य की कानून-व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बने हुए है। सीमा से सटे इलाकों में तस्करी के कारण अक्सर हिंसा और तनाव की खबरें आती रहती हैं। भाजपा ने अपने चुनावी वादों में इस मुद्दे को प्रमुखता से रखा था। अब जनता की नजरें इस बात पर हैं कि सरकार इस संगठित अपराध को कैसे रोकती है। तस्करी के इस नेटवर्क में कई अपराधी शामिल हैं, जो सुरक्षा घेरे को तोड़कर पशुओं को सीमा पार ले जाते हैं। यह समस्या केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य और देश की सुरक्षा से भी जुड़ी है। तस्करी के बढ़ते मामलों ने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं।

3- महिला सुरक्षा सुनिश्चित करना

पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार के सामने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती है। राज्य में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को देखते हुए भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में दुर्गा सुरक्षा स्क्वॉड बनाने का वादा किया था। बता दें कि यह एक विशेष पुलिस दस्ता होगा जो केवल महिलाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित रहेगा। इस दस्ते का मुख्य काम सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी रखना और संकट के समय महिलाओं की तुरंत मदद करना होगा। बंगाल में महिलाओं को भयमुक्त और सुरक्षित माहौल देना नई सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार का लक्ष्य है कि इस विशेष दस्ते के जरिए अपराधियों में डर पैदा किया जाए।

4- बंगाल में समान नागरिक संहिता लागू करना

पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन के बाद अब समान नागरिक संहिता को लागू करना एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने है। भाजपा ने हमेशा से ही यूसीसी को अपने मुख्य एजेंडे में शामिल रखा है। बंगाल जैसे बड़े और विविध आबादी वाले राज्य में इसे जमीन पर उतारना काफी जटिल काम होगा। क्योंकि यहां अलग-अलग समुदायों और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। ऐसे में सभी के लिए एक समान कानून बनाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए शुभेंदु सरकार को कई कड़े और बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस दिशा में कदम कैसे आगे बढ़ाती है।

5- सिंडिकेट-कट मनी पर लगाम लगाना

पश्चिम बंगाल में नई सरकार के सामने सबसे बड़ी और जटिल चुनौती सिंडिकेट और कट मनी की पुरानी समस्या को खत्म करना है। राज्य में लंबे समय से विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इसके अलावा, कट मनी यानी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के बदले होने वाली अवैध वसूली ने आम जनता को परेशान कर रखा है। गरीब लोगों तक पहुंचने वाली आर्थिक मदद का एक हिस्सा बिचौलिए डकार जाते हैं। इस कमीशनखोरी के कारण राज्य में विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई है और सरकारी खजाने को भी भारी नुकसान होता है। भाजपा ने चुनाव के दौरान इस भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का वादा किया था। शुभेंदु सरकार के लिए इस समस्या का समाधान करना एक बड़ी परीक्षा होगी।

पीए मोदी का विनम्र अंदाज, बंगाल की जनता को किया दंडवत प्रणाम

कोलकाता। एक ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन के तहत, शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि द्वारा पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अधिकारी राज्य के नौवें मुख्यमंत्री बने हैं, जिससे ममता बनर्जी के 2011 में शुरू हुए 15 साल के शासन का प्रभावी रूप से अंत हो गया है। यह ऐतिहासिक समारोह तृणमूल कांग्रेस के एक दशक से अधिक के शासन के बाद राज्य के नेतृत्व में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। शपथ ग्रहण समारोह के अलावा, कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्शकों के प्रति किया गया हावभाव चर्चा का मुख्य विषय बन गया। गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, प्रधानमंत्री ने भीड़ के सामने पूरी तरह से सिर झुकाया, इस भाव ने ऐतिहासिक आयोजन के लिए एकत्रित हजारों लोगों के मन पर गहरा प्रभाव डाला। इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान भाजपा के वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं में से एक, अनुभवी भाजपा कार्यकर्ता मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। 98 वर्ष की आयु में भी, सरकार स्वतंत्रतोत्तर भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े शुरुआती जमीनी स्तर के नेताओं में से एक हैं। यह समारोह उस दिन आयोजित हुआ जो बंगाली पंचांग के अनुसार गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती के साथ संयोगवश और भी महत्वपूर्ण हो गया। इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त, भाजपा शासित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय पार्टी के शीर्ष नेता भी इस ऐतिहासिक परिवर्तन के साक्षी बनने के लिए मौजूद थे। मोदी ने पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के प्रतिष्ठित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

टीएमसी की हार पर अभिषेक बनर्जी का बड़ा आरोप, कहा-

वोटर लिस्ट से 30 लाख नाम हटाए गए

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए दावा किया कि लगभग 30 लाख वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। उन्होंने कहा कि पार्टी को कठिन चुनाव का सामना करना पड़ा और उन्होंने सरकारी एजेंसियों और चुनाव आयोग सहित कई संस्थानों पर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाया। यह घटनाक्रम भाजपा के विधायक दल के नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा आज राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के ठीक बाद सामने आया है, जो पश्चिम बंगाल में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है।

एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हमने एक बेहद कठिन चुनाव लड़ा है, जिसमें कथित तौर पर लगभग 30 लाख वास्तविक मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, हमने कई सरकारी एजेंसियों और भारतीय चुनाव आयोग द्वारा घोर पक्षपातपूर्ण आचरण देखा। निष्पक्ष रूप से कार्य करने वाली लोकतांत्रिक संस्थाएँ समझौता करती हुई प्रतीत हुईं, जिससे पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठते हैं। उन्होंने मतगणना प्रक्रिया और ईवीएम के संचालन सहित चुनावी प्रक्रिया पर भी चिंता व्यक्त की।

उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ चुनाव के बाद हिंसा और धमकी का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में कानूनी और लोकतांत्रिक उपायों का पालन करते हुए उनके साथ खड़ी रहेगी। पोस्ट में लिखा था कि मतगणना प्रक्रिया से लेकर ईवीएम के संचालन और आवागमन से जुड़े आरोपों, नियंत्रण इकाइयों की विसंगतियों तक, कई परेशान करने वाली घटनाओं ने लाखों लोगों को यह सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है कि क्या जनता के वास्तविक जनादेश का सम्मान किया गया है। मैंने पहले ही मतगणना केंद्रों से सीसीटीवी फुटेज जारी करने और वीवीपीएटी पर्चियों की पारदर्शी गिनती की मांग की है ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके और हर संदेह का खुले तौर पर और ईमानदारी से समाधान किया जा सके।

पोस्ट में आगे लिखा था कि ममता बनर्जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों और जनता के अधिकारों और गरिमा के लिए हमारी लड़ाई बिना किसी डर और बिना किसी समझौते के जारी रहेगी। मैं तृणमूल के हर समर्थक और कार्यकर्ता से इस कठिन समय में मजबूत और एकजुट रहने का आग्रह करता हूं। यदि किसी को चुनाव के बाद हिंसा, धमकी या डराने-धमकाने का सामना करना पड़ा है, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे मुझसे संपर्क करें और अपनी जानकारी साझा करें या मुझे संदेश भेजें। मैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और हर संभव कानूनी और लोकतांत्रिक उपाय अपनाने के लिए अपनी पूरी क्षमता से प्रयास करूंगा। मैं सत्य की जीत सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों सरकारें अब पश्चिम बंगाल की जनता के हितों में ईमानदारी से काम करें, इस लड़ाई में तृणमूल के हर कार्यकर्ता और समर्थक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा ने 207 सीटें जीतीं, जबकि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने 15 वर्षों तक राज्य पर शासन करने के बाद केवल 80 सीटें हासिल कीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव ला दिया है। ममता बनर्जी का लंबा वर्चस्व समाप्त हो गया और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 207 सीटों के साथ सत्ता में आई।

खेल
प्रमुख समाचार

चेन्नई सुपर किंग और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच भिड़ंत आज

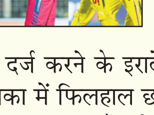

चेन्नई। चेन्नई सुपर किंग (सीएसके) की टीम आईपीएल 2026 में अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। अंक तालिका में फिलहाल छठे स्थान पर मौजूद सीएसके के लिए अब हर मैच बेहद अहम हो गया है। टूर्नामेंट अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है और ऐसे में पांच बार की चैंपियन टीम कोई गलती नहीं करना चाहेगी। दूसरी तरफ एलएसजी की टीम सबसे निचले पायदान पर है और उसकी प्लेऑफ की उम्मीदें बेहद कमजोर नजर आ रही हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन इस सीजन उतार-चढ़ाव भरा रहा है। टीम घरेलू और बाहरी दोनों मैदानों पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही। हालांकि अब चेपॉक में वापसी के साथ टीम एक बार फिर लय हासिल करना चाहेगी। सीएसके का बल्लेबाजी क्रम काफी हद तक संजू सैमसन पर निर्भर रहा है। उन्होंने कई मौकों पर शानदार पारियां खेलकर टीम को जीत दिलाई। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछले मैच में सैमसन ने 52 गेंदों में 87 रन की मैच जिताऊ पारी खेली थी। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स का यह सीजन बेहद खराब रहा है। टीम ने 10 मैचों में सिर्फ तीन जीत दर्ज की हैं और अंक तालिका में सबसे नीचे है। कप्तान ऋषभ पंत भी बल्ले से उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। हालांकि आरसीबी के खिलाफ पंत ने 10 गेंदों में 32 रन की तेज पारी खेली थी, लेकिन पूरे सीजन में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। एलएसजी के लिए पिछले मुकाबले में मिचेल मार्श ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 56 गेंदों में 111 रन बनाए थे। उनकी इस पारी की बदौलत टीम ने आरसीबी को 9 रन से हराकर लगातार छह हार का सिलसिला खत्म किया। इस जीत ने लखनऊ की प्लेऑफ की बची-खुची उम्मीदों को भी जिंदा रखा है। अब टीम चाहेगी कि चेन्नई के खिलाफ भी जीत की लय बरकरार रखी जाए।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान
प्रमुख समाचार

सस्ते होंगे देव लैबटेक के शेयर कंपनी ने किया ऐलान

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में अगले सप्ताह एक बार फिर हलचल बढ़ने वाली है। शेयर बाजार से कमाई करने वाले निवेशकों के लिए 'कॉर्पोरेट एक्शन' बहुत मायने रखते हैं। इसी कड़ी में अगले हफ्ते एक प्रमुख कंपनी देव लैबटेक अपने शेयरों को टुकड़ों में बांटने जा रही है, जिसे बाजार की भाषा में 'स्टॉक स्प्लिट' कहा जाता है। बीएसई पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, कंपनी ने अपने शेयर की फेस वैल्यू को 10 रुपये से घटाकर 5 रुपये करने जा रही है। इस कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए स्टॉक स्प्लिट का फैसला लिया है, जिसकी तारीखें अब बेहद करीब आ चुकी हैं। आधिकारिक डेटा के मुताबिक, देव लैबटेक (सिक्योरिटी कोड: 543848) ने इस कॉर्पोरेट एक्शन के लिए 15 मई 2026 की तारीख तय की है। यही दिन कंपनी के लिए 'एक्स-डेट' और 'रिकॉर्ड डेट' दोनों होगा।

महंगी हुईं शाकाहारी और मांसाहारी थाली

नईदिल्ली। अप्रैल महीने में घर पर बनने वाली शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह की थालियां महंगी हो गईं। क्रिसिल इंटेलीजेंस की मासिक 'रोटी राइस रेट' रिपोर्ट के अनुसार, साल-दर-साल आधार पर थाली की लागत में करीब 2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके पीछे टमाटर, वनस्पति तेल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में उछाल मुख्य वजह रही। रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण भारत में खेती का रकबा घटने से टमाटर का उत्पादन प्रभावित हुआ, जिससे इसकी कीमतों में 38त्न की तेज बढ़ोतरी हुई। वहीं, वैश्विक सप्लाई दबाव के चलते वनस्पति तेल और एलपीजी सिलेंडर भी 7-7% महंगे हो गए। क्रिसिल इंटेलीजेंस के डायरेक्टर पुष्न शर्मा ने कहा कि खाद्य सामग्री और ईंधन की बढ़ती लागत से शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थालियों की कीमतों में बढ़ोतरी इसी कारण हुई है।

31 तक खाते में रखें 436 रुपए वरना बंद हो सकता है बीमा कवर

नईदिल्ली। केंद्र सरकार की लोकप्रिय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। यह योजना कम प्रीमियम में जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करती है और खासतौर पर निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी। इस योजना का लाभ जारी रखने के लिए 31 मई तक अपने बैंक खाते में कम से कम 436 रुपए जरूर रखें। यह एक साल की टर्म इंश्योरेंस योजना है, जिसके तहत 18 से 50 वर्ष तक के बैंक खाताधारकों को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है। बीमाधारक की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर यह राशि नामांकित व्यक्ति को दी जाती है। योजना में पहले से मौजूद बीमारियों पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। इस योजना के लिए सालाना सिर्फ 436 रुपए प्रीमियम देना होता है। यह राशि सीधे बैंक या डाकघर खाते से ऑटो-डेबिट हो जाती है।

एक्जिम बैंक का वित्त वर्ष 25-26 में शुद्ध लाभ 32% बढ़ा

नई दिल्ली। भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) का वित्त वर्ष 2025-26 में शुद्ध लाभ 32 प्रतिशत बढ़कर 4,273 करोड़ रुपए रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 में 3,243 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। एक्जिम बैंक ने बयान में बताया कि पूरे वित्त वर्ष (2025-26) के दौरान उसका कुल कारोबार 13.31 प्रतिशत बढ़कर 4.50 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जबकि शुद्ध ऋण पोर्टफोलियो लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2.07 लाख करोड़ रुपए रहा। आलोच्य वित्त वर्ष के दौरान बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता में भी सुधार दर्ज किया गया है। सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घटकर 0.57 प्रतिशत पर आ गया। वहीं शुद्ध एनपीए 0.14 प्रतिशत से घटकर 0.01 प्रतिशत पर रहा।

इंडो पैसेफिक में भारत कैसे बनता जा रहा है सबसे बड़ी रणनीतिक शक्ति?

नीरज कुमार दुबे

21वीं सदी की वैश्विक राजनीति का केंद्र तेजी से इंडो पैसेफिक क्षेत्र बनता जा रहा है। हम आपको बता दें कि यह वही भू क्षेत्र है जहां विश्व की लगभग 65 प्रतिशत आबादी रहती है, वैश्विक सकल उत्पादन का लगभग 62 प्रतिशत हिस्सा उत्पन्न होता है और दुनिया के करीब आधे समुद्री व्यापार का संचालन होता है। ऐसे रणनीतिक और आर्थिक महत्व वाले क्षेत्र में भारत की भूमिका पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ी है। यह केवल संयोग नहीं बल्कि भारतीय विदेश नीति की दूरदर्शिता, संतुलन और आक्रामक कूटनीति का परिणाम है।

हम आपको बता दें कि इंडो पैसेफिक में भारत की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र वैश्विक समुद्री व्यापार की जीवन रेखा है। विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग इसी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। भारत के कुल विदेशी व्यापार का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा समुद्री मार्गों से संचालित होता है। इस कारण हिंद महासागर की सुरक्षा और समुद्री मार्गों की स्थिरता भारत के लिए केवल रणनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि आर्थिक आवश्यकता भी है। भारत ने इसी दृष्टि से अपनी विदेश नीति को समुद्री शक्ति, समुद्री संपर्क और समुद्री सहयोग से जोड़ा है।

भारत की भौगोलिक स्थिति भी उसे इस क्षेत्र में स्वाभाविक शक्ति बनाती है। भारत हिंद महासागर के मध्य में स्थित है और मलक्का जलडमरूमध्य जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के निकट है। यह वही मार्ग है जिससे एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच भारी मात्रा में व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित द्वीपों और समुद्री मार्गों की निगरानी करने की क्षमता भारत को इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था में केंद्रीय भूमिका प्रदान करती है।

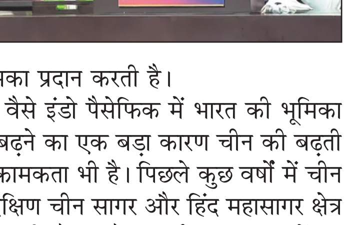

वैसे इंडो पैसेफिक में भारत की भूमिका के बढ़ने का एक बड़ा कारण चीन की बढ़ती आक्रामकता भी है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सैन्य और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार किया है। बंदरगाह निर्माण, समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और ऋण आधारित अवसंरचना परियोजनाओं के माध्यम से चीन ने इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया है। इस परिस्थिति में अनेक देशों ने भारत को संतुलन स्थापित करने वाली शक्ति के रूप में देखा है। यही कारण है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों ने भारत के साथ रणनीतिक सहयोग को मजबूत किया है। क्वॉड सुरक्षा संवाद जैसे मंचों के माध्यम से समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, प्रौद्योगिकी सहयोग और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग विकसित हुआ है। इससे भारत की सामरिक और कूटनीतिक क्षमता दोनों में वृद्धि हुई है। भारतीय विदेश नीति की सफलता इस बात में भी दिखाई देती है कि भारत ने इंडो पैसेफिक को केवल सैन्य दृष्टिकोण से नहीं देखा बल्कि उसे आर्थिक और विकासात्मक सहयोग के मंच के रूप में भी विकसित किया। भारत ने आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। एक्ट ईस्ट नीति के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार, निवेश और संपर्क के नए मार्ग विकसित किए गए हैं। इसके अलावा, भारत ने क्षेत्रीय संगठनों में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। हिंद महासागर रिम संघ, बिमस्टेक और अन्य बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से भारत समुद्री सहयोग, व्यापार और संपर्क को बढ़ावा दे रहा है। इन मंचों के माध्यम से भारत क्षेत्रीय विकास और सामूहिक सुरक्षा की नीति को आगे बढ़ा रहा है।

साथ ही समुद्री अवसंरचना के क्षेत्र में भी भारत ने बड़े स्तर पर निवेश शुरू किया है। सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत देश के बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, समुद्री परिवहन का विस्तार और तटीय आर्थिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत लगभग एक सौ बीस अरब डॉलर के निवेश की योजना बनाई गई है। इसके अलावा भारत ने दीर्घकालिक दृष्टि से समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए विशाल निवेश योजनाएं तैयार की हैं जिनका उद्देश्य भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाना है।

प्रधानमंत्री मोदी ने छुए माखनलाल सरकार के पैर, वो भाजपा के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं

शुभेंदु की शपथ के साक्षी बने साय

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए सीएम के तौर पर पद की शपथ ली। शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम विष्णु देव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी शामिल हुए। दोनों नेताओं ने शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात कर उनको बधाई दी। सीएम और डिप्टी सीएम ने कहा कि अब बंगाल में बदलाव होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह जनादेश केवल सरकार बदलने का नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल में विकास, सुशासन और नई कार्यसंस्कृति की स्थापना का जनसंकल्प है।

विष्णु देव साय ने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन तथा मजबूत नेतृत्व में डबल इंजन सरकार अब बंगाल के विकास की नई गाथा लिखेगी। इस सरकार के माध्यम से युवाओं को भरपूर रोजगार, किसानों को समृद्धि, मातृशक्ति को सशक्त अवसर और हर वर्ग को न्यायपूर्ण विकास मिलेगा। आपके कुशल नेतृत्व में बंगाल विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। माताओं-बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, युवाओं को उनके सपनों के अनुरूप रोजगार मिलेगा और बांग्ला एक बार फिर सच्चे अर्थों में सोनार बांग्ला बनेगा।

विजय शर्मा ने कहा मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन तथा आपके सक्षम नेतृत्व में पश्चिम बंगाल विकास, सुशासन, सुरक्षा और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा तथा प्रदेश प्रगति के नए अध्याय लिखेगा।

केदार कश्यप ने कहा 98 वर्ष की आयु में भी, श्री माखनलाल सरकार आज़ादी के बाद के भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े शुरुआती ज़मीनी स्तर के नेताओं में से एक हैं। 1952 में, उन्हें कश्मीर में भारतीय तिरंगा फहराने के आंदोलन के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ होने पर गिरफ्तार किया गया था।

जानिए कौन हैं माखनलाल सरकार

शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मंच पर जब पीएम मोदी पहुंचे, तब वहां पर 98 साल के माखनलाल सरकार भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने मंच पर जाते ही माखनलाल सरकार के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। पश्चिम बंगाल के सबसे वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता माखनलाल सरकार ने पीएम मोदी को गले लगा लिया। उस नजारे को देख कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मौजूद लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार तालियों से पीएम मोदी और माखनलाल सरकार का धन्यवाद और स्वागत किया। माखनलाल सरकार पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं।

भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक वो साल 1952 में स्वर्गीय डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ऐतिहासिक कश्मीर यात्रा के दौरान उनके साथ रहे। माखनलाल सरकार लंबे समय से राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं और जेल भी जा चुके हैं। 1

980 में बीजेपी की स्थापना के बाद उन्होंने बंगाल में पार्टी और संगठन के विस्तार में काफी अहम भूमिका निभाई है।

सफल होना है तो ईर्ष्या नहीं प्रतिस्पर्धा करें...

रायपुर। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा चौबे कालोनी रायपुर में आयोजित समर कैम्प में रायपुर संचालिका ब्रह्माकुमारी सविता दीदी ने आज बच्चों को जीवन में नैतिकता विषय पर अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित किया। उन्होंने बच्चों को स्वयं में विशेषताएं भरकर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत ही उपयोगी सुझाव दिए।

ब्रह्मकुमारी सविता दीदी ने कहा कि किसी की सफलता को देखकर उससे ईर्ष्या नही करें। सफल होना है तो रिस (ईर्ष्या) नहीं रेस (प्रतिस्पर्धा) करो। हरेक बच्चे को अपने जीवन में कोई लक्ष्य अवश्य निर्धारित करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करने से आगे बढ़ने का मार्ग सुनिश्चित हो जाता है। इससे मन यहाँ-वहाँ भटकने की अपेक्षा शान्त चित्त होकर एक ही दिशा में अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करने पर विचार करेगा। जीवन में लक्ष्य नहीं बनाया तो उम्र में बड़े तो हो जाएंगे किन्तु सफल व्यक्ति नहीं कहलाएंगे।

उन्होंने आगे कहा कि जैसे दुनिया में बाह्य शरीर को सजाने सँवारने के लिए ब्यूटी पार्लर होते है उसी प्रकार अपने आंतरिक स्वरूप को निखारने के लिए भी ऐसे पार्लर की आवश्यकता है जहाँ अंतर्मन को दिव्य गुणों और मानवीय मूल्यों से सजाया जा सके। उन्होंने बतलाया कि अपने आचरण, व्यवहार और सोच को रचनात्मक बनाकर बुरी आदतों, व्यसनों आदि से स्वयं को मुक्त करना ही सच्चे अर्थों में व्यक्तित्व का विकास करना है। हमारे शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए राजयोग मेडिटेशन की साधना बहुत ही उपयोगी है।

ग्रीन गोल्ड वनोपज की चमक से संवरती ग्रामीण अर्थव्यवस्था

रायपुर। छत्तीसगढ़, जिसे हर्बल स्टेट के रूप में जाना जाता है, आज अपनी समृद्ध वन संपदा और दूरदर्शी शासकीय नीतियों के बल पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे रहा है। यहां के वनों से प्राप्त होने वाला ग्रीन गोल्डस् अब केवल स्थानीय उपयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक बाज़ारों में अपनी चमक बिखेर रहा है। छत्तीसगढ़ की यह पहल न केवल वनों का संरक्षण कर रही है, बल्कि ग्रामीण समाज में स्वावलंबन, आत्मविश्वास और आर्थिक सुरक्षा की एक नई चेतना का संचार कर रही है।

'ग्रीन गोल्ड' (हरा सोना) वनों की असली पूँजी छत्तीसगढ़ में वनोपज को श्हरा सोनाश् कहा जाता है, जो राज्य की आर्थिक रीढ़ है। तेंदूपत्ता एवं बांस बहुमुखी उपयोगिता के कारण इन्हें प्रमुखता से श्हरा सोनाश् माना जाता है। लाख, शहद और दुर्लभ औषधीय पौधों के साथ-साथ सागौन, साल, बीजा और शीशम जैसे कीमती वृक्ष यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। आधुनिक प्रसंस्करण के माध्यम से इन कच्चे माल को उच्च मूल्य के उत्पादों में बदला जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और वन मंत्री श्री केदार कश्यप द्वारा लोकार्पित यह इकाई वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था का पावरहाउस है। आंवला, बेल, गिलोय और अश्वगंधा जैसे उत्पादों को जूस, कैंडी और हर्बल पाउडर में परिवर्तित किया जाता है। वैज्ञानिक भंडारण यहाँ 20 हजार मीट्रिक टन क्षमता वाले अत्याधुनिक गोदाम हैं, जो उपज को सुरक्षित रखते हुए संग्राहकों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाते हैं। छत्तीसगढ़ हर्बल्स स्थानीय से वैश्विक तक राज्य सरकार का यह आधिकारिक ब्रांड शुद्धता और प्राकृतिक उत्पादों का पर्याय बन चुका है।

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 12-13 मई को, रणनीति पर मंथन

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक 12 और 13 मई को आयोजित की जाएगी। बैठक में संगठन की आगामी कार्ययोजना, राजनीतिक गतिविधियों और संगठनात्मक रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। पहले दिन 12 मई को रायपुर स्थित ठाकरे परिसर में शाम 6 बजे कोर कमेटी की बैठक आयोजित होगी। यह बैठक मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के असम सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से लौटने के बाद होगी। इसके बाद शाम 7:30 बजे से प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक शुरू होगी। दूसरे दिन 13 मई को सुबह 10 बजे प्रदेश कार्यसमिति की मुख्य बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में संगठन के वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा और आगामी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति तय की जाएगी।

भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मार्कण्डेय ने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय मौजूद रहेंगे। बैठक में संगठन विस्तार, आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावी और संगठनात्मक गतिविधियों के लिए दिशा-निर्देश देगा।

बारिश से बढ़ी आरसीबी-मुंबई मुकाबले की चिंता, भीगा स्टेडियम

रायपुर। राजधानी के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शनिवार को अचानक मौसम बदलने से खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रशंसकों की चिंता बढ़ गई। मुंबई इंडियंस की टीम के अभ्यास सत्र के दौरान तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद मैदानकर्मियों ने तुरंत पिच को कवर कर सुरक्षित किया। अहम मुकाबला खेला जाना है। ऐसे में लगातार बदलते मौसम और बारिश की संभावना ने मैच को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है। बारिश शुरू होते ही अभ्यास सत्र कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। मैदान पर पानी जमा होने से ग्राउंड स्टाफ लगातार पिच और आउटफील्ड को सुरक्षित रखने में जुटा रहा। हालांकि कुछ देर बाद बारिश थमी, लेकिन मौसम पूरी तरह साफ नहीं हो पाया मौसम विभाग ने भी रविवार को हल्की

से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में मैच के दौरान भी रुकावट आने की आशंका बनी हुई है। क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें अब मौसम पर टिकी हैं और सभी को उम्मीद है कि मुकाबला बिना किसी बाधा के पूरा हो सके। आईपीएल के इस अहम मैच को लेकर दोनों टीमों ने तैयारियां तेज कर रखी हैं। अंक तालिका के लिहाज से भी यह मुकाबला महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसलिए बारिश का असर मैच की रणनीति पर भी पड़ सकता है। फिलहाल स्टेडियम प्रबंधन और आयोजन समिति मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

18 लाख आवास देने का सरकार का दावा हवा हवाई: बैज

रायपुर। सुशासन तिहार में सरकार के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की पोल खुल गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि गरियाबंद जिले देवभोग के माडागांव के सुशासन तिहार में कमार परिवार ने प्रधानमंत्री आवास के लिए जिला पंचायत सी.ई.ओ. के पैर में गिर कर आवास की मांग किया। यह घटना भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री आवास पर किये गये दावों की जमीनी हकीकत है। कमार जनजाति विशेष संरक्षित जनजाति है, इन्हें

राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है तथा सभी शासकीय योजनाओं के केंद्र बिंदु में इन्हें रखा जाता है। जब कमार जनजाति का परिवार अपने प्रधानमंत्री आवास के लिए अधिकारी के सामने दंडवत होने को मजबूर है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास की क्या हकीकत होगी? यह घटना सरकार के लिए शर्मनाक है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि साय सरकार 18 लाख आवास पर श्वेत पत्र जारी करे। भाजपा सरकार 18 लाख आवास स्वीकृत होने का झूठा दावा करती है, जबकि सच्चाई यह है कि साय सरकार गरीबों को आवास देने के नाम से धोखाधड़ी की है, जो भी आवास बने है और जो बन रहे है वो कांग्रेस सरकार के दौरान स्वीकृत हुए थे।

सुशासन तिहार में खोली दावों की पोलः ठाकुर

रायपुर। भाजपा विधायक शकुंतला पोर्ते के अधिकारियों पर काम नही करने के आरोप पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधायक शकुंतला पोर्ते ने सुशासन तिहार के मंच से सुशासन के दावों की पोल खोल दी है। अधिकारियों, कर्मचारियों पर जनता का काम नहीं करने का आरोप लगाया है, जनता के श्राप से घमंड टूटने की बात कही है। पोर्ते भूल गई जनता ने

अधिकारियों को नहीं चुना है बल्कि भाजपा को चुनकर सरकार बनाने का अवसर दिया है और ढाई साल की भाजपा सरकार जनता के लिए ट्रबल इंजन साबित हो गई है, हर विभाग में अराजकता फैल गई है, जनता की समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। इसकी मुख्य वजह कमजोर, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी में डूबी भाजपा सरकार है। सुशासन तिहार को ढकोसला बताते हुए कहा कि पिछले साल हुई सुशासन तिहार में 44 लाख से अधिक आवेदन आये थे जिसमें राजस्व विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, परिवहन विभाग, बिजली विभाग, जल संसाधन विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, पंचायत विभाग, कृषि विभाग, खाद्य विभाग सहित लगभग सभी विभागों से सम्बंधित समस्याओं को जनता ने रखा था।

पीएम मोदी राज में महंगाई बेतहाशा बढ़ी : शुक्ला

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, महंगाई से देश के नागरिकों की कमर टूटती जा रही है। 2014 में जो गैस का सिलेंडर 410 रु. का था, आज वह 980 रु. के पार है वह भी मिल नहीं रहा। पेट्रोल के दाम 70 रु. प्रति लीटर से बढ़कर 102 रु. प्रति लीटर के पार हो गए हैं जबकि डीजल के दाम 55 रु. प्रति लीटर से

बढ़कर 100 रु. प्रति लीटर के करीब पहुंच गए हैं। मोदी सरकार ने महंगाई से जूझ रही जनता एवं मंदी की मार झेल रहीं व्यवसायिक संस्थानो, उद्योगों पर कुठाराघात किया है।घरेलू कामर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ोत्तरी कर दिया एक मुश्त 993 रु की बढोत्तरी एवं प्रवासी श्रमिको एवं गरीब जनता द्वारा उपयोग किये जाने वाले 5 किलो वाली गैस सिलेंडर के दाम में 261 रु की वृद्धि कर दी है।बीते पांच माह में कामर्शियल सिलेंडर के दाम में 1510 रु की वृद्धि हुई है जनवरी में 111रु फरवरी में 50रु मार्च में दो बार मिलाकर 146 रु अप्रैल में 218 रु एवं मई में 993 रु की वृद्धि हुई है, अब घरेलू गैस एवं पेट्रोल डीजल के दाम में भी वृद्धि की संभावना है। इसका सीधा असर आम जनता, उद्योग, होटल रेस्टोरेंट, ढाबा एवं कामर्शियल गैस उपयोग करने वाले संस्थानों पर पड़ेगा।

पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने में अक्षम सरकार : वर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों (सोसाइटियों) के माध्यम से किसानों को मिलने वाले उर्वरकों (खाद) की लिमिट का रेशियो 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने के सरकार के फैसले को किसान विरोधी निर्णय बताते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि किसानों को आगामी खरीफ सीजन के लिए खाद उपलब्ध कराने में अपनी नाकामी को छुपाने के

लिए भाजपा सरकार ने सोसायटियों से नकदी और खाद के ऋण का रेसियो ही बदल दिया है, अब नई व्यवस्था के अनुसार, कृषि ऋण में अब 70 प्रतिशत नकद राशि और केवल 30 प्रतिशत वस्तु के रूप में दी जा रही है। पूर्व में, किसानों को ऋण का 60 प्रतिशत नगदी और 40 प्रतिशत खाद, बीज के रूप में मिलते थे। हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने एन पी के की कीमत 180 रुपए प्रति बोरी और पोटास की कीमतों में 300 रुपए प्रति बोरी भारी भरकम वृद्धि की है अब खाद की लिमिट का कम होना किसानों के लिए एक गंभीर संकट है। सहकारी समितियों में खाद की कमी, मूल्य वृद्धि और वितरण के तरीके में बदलाव से किसान परेशान हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि सहकारी समितियों में डीएपी और यूरिया की भारी कमी के कारण किसान पहले से ही परेशान हैं।

न्याय दिलाने सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र अपील करेंः धनेन्द्र साहू

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री छ.ग.शासन ने मुख्यमंत्री जी को पत्र प्रेषित करते हुए प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा है कि हाल ही में हाई कोर्ट द्वारा नक्सली घटनाओं के आरोपियों को शासन के द्वारा नियुक्त जांच एजेंसी एवं अधिवक्ताओं की टीम भी तथ्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ होने के कारण की टिप्पणी करते हुए बरी कर दिया गया । यह फैसला एक बार फिर चर्चा

का विषय बन गया है। जब भी ऐसी बड़ी घटनाओं में बरी होने की खबर आती है, तो यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या हमारी जांच एजेंसियां साक्ष्य जुटाने में कमजोर रही हैं या निर्दोष लोग वर्षों तक जेल में बंद रहे? । अक्सर यह देखा गया है कि नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में डर के मारे गवाह सामने नहीं आते। बिना ठोस सबूतों और गवाहों के, अदालत के पास बरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। यह जांच प्रणाली पर एक सवाल खड़ा करता है जो कि जांच में कमी को दर्शाता है ।

अगर कोई निर्दोष वर्षों तक जेल में रहता है और बाद में बरी होता है, तो उसके पुनर्वास की जिम्मेदारी किसकी है? कोर्ट का फैसला व्यक्ति की आजादी का सम्मान करता है।

अधिकारी से लाइनमेन तक हों एआई तकनीक से लैस

बिजली सप्लाई को नई तकनीक से बेहतर बनाएं : सुबोध सिंह

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज् के अध्यक्ष श्री सुबोध कुमार सिंह ने डंगनिया स्थित मुख्यालय में जनरेशन, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बिजली हर व्यक्ति के जीवन की मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है और उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना पावर कंपनीज् की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

श्री सिंह ने अधिकारियों से कहा कि विद्युत व्यवस्था को आधुनिक, तेज एवं उपभोक्ता केंद्रित बनाने के लिये नवीन टेक्नोलॉजी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिकतम उपयोग किया जाए।

उन्होंने डाटा बेस्ड डिसिजन मेकिंग पर जोर देते हुए कहा कि आधुनिक एआई तकनीक का उपयोग कर विद्युत आपूर्ति, फॉल्ट मॉनिटरिंग, लोड प्रबंधन, उपभोक्ता शिकायत निवारण एवं सिस्टम मॉनिटरिंग को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।श्री सिंह ने कहा कि पावर कंपनीज् में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नई तकनीकों एवं आधुनिक कार्यप्रणाली से लैस किया जाना चाहिए, ताकि कार्य क्षमता, मॉनिटरिंग सिस्टम और उपभोक्ता सेवाओं की गुणवत्ता में व्यापक सुधार किया जा सके।उन्होंने तीनों कंपनियों के अधिकारियों की अलग-अलग बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में नए भवन निर्माण कार्यों में तेजी लाने, लंबित परियोजनाओं को समय-सीमा में पूर्ण करने तथा उपभोक्ता सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए।

अध्यक्ष श्री सिंह ने टोल फ्री कॉल सेंटर नंबर 1912 को और अधिक दक्ष बनाने तथा शिकायतों के निराकरण के रिस्पांस टाइम में तेजी लाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना पावर कंपनीज् की प्राथमिक जिम्मेदारी है। बैठक में जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक एसके कटियार, ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक भीमसिंह कंवर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रोजेक्ट छाँवः कर्मियों और उनके परिवारों के लिए व्यापक स्वास्थ्य एवं सेवा शिविर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिला प्रशासन का नवाचार 'प्रोजेक्ट छाँव' के पहल के तहत आज सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, रायपुर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम रायपुर के 1000 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी और उनके परिवारजनों ने विभिन्न स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श का लाभ लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर मुख्य सचिव एवं जिले की प्रभारी सचिव ऋचा शर्मा शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र से जुड़कर जिला प्रशासन नवाचार कर रहा है। शासकीय सेवा के अतिरिक्त समाज के लिए

कार्य करना प्रेरणादाई है। यह पहल सभी शासकीय कर्मचारियों और उनके परिवारजनों के लिए सराहनीय है। जिला कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के नेतृत्व में जिले में इस प्रकार नवाचार किए जा रहे हैं उसे आगे बढ़ाएं। मैं इस अभिनव पहल के लिए जिला प्रशासन को बधाई देती हूँ।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि जब हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, तभी हम अच्छे से कार्य कर पाएंगे। इसी कड़ी में सभी शासकीय कर्मचारी-अधिकारियों के परिवार का स्वास्थ्य परीक्षण हो सके, इसके लिए इस पहल की शुरुआत की गई थी। सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी निस्वार्थ भाव से शासन के लिए कार्य करते हैं। सभी कर्मचारी अपने परिवार के साथ आते हैं और उनका निःशुल्क उच्च स्तरीय जांच एवं उपचार किया जाता है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.